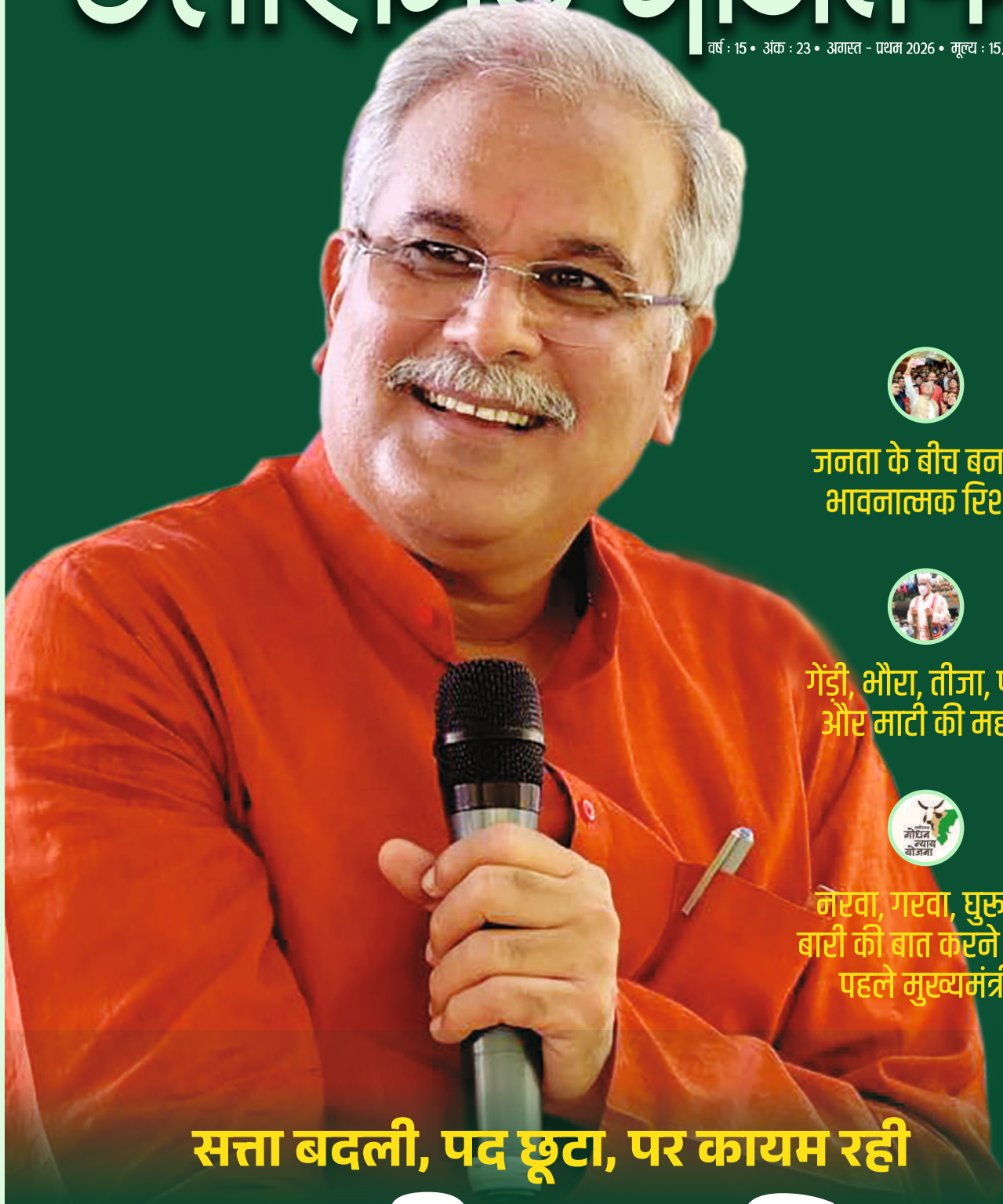


छत्तीशगढ श्वाजतक

वर्ष : 15 • अंक : 23 • अगस्त - प्रथम 2026 • मूल्य : 15/-



जनता के बीच बनाया
भावनात्मक रिश्ता



गेंडी, भौरा, तीजा, पोरा
और माटी की महक



नेरवा, गरवा, घुरुवा,
बारी की बात करने वाले
पहले मुख्यमंत्री

सत्ता बदली, पद छूटा, पर कायम रही

कका की मकबूलियत



स्व. सरदार बीर सिंह जी

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा।

80^{वें}
स्वतंत्रता
दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं।

इंद्रजीत सिंह छोट्

संरक्षक -

- छवीसगढ़ पोवर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन
- जिला हॉकी संघ दुर्ग
- छवीसगढ़ सीमेंट वेलफेयर एसोसिएशन
- छवीसगढ़ बलकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
- भिलाई सिविल कंस्ट्रक्टर वेलफेयर सोसाइटी

अध्यक्ष -

- भिलाई ट्रक ड्रेजर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन
- वृष सिखा सेवा समिति, भिलाई
- रसमझ परिवहन संघ
- न्यू गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छवीसगढ़
- सर्व समाज कल्याण समिति



छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 15 • अंक : 23 • अगस्त-प्रथम 2026

संपादक :	लखन लाल
सलाहकार संपादक :	सादात अनवर
कार्यकारी संपादक :	दीपक रंजन दास
विशेष प्रतिनिधि :	मंजुला कौशिक
कानूनी सलाहकार :	गिरीशचंद्र शर्मा
प्रबंध संपादक :	डॉ. डी.पी. देशमुख

सरगुजा प्रभारी :	अमरेश्वर दुबे
फोटो जर्नलिस्ट :	पी. मोहन

प्रतिनिधि :-

रायपुर :	भूपेन्द्र वर्मा
दुर्ग :	रामशरण कौशिक
राजनांदगांव :	राहुल गौतम
कबीरधाम :	सुरेश प्रसाद गुप्ता
कोरबा :	अजय कुमार
जांजगीर-चांपा :	समयदास अविनाशी
कटघोरा :	विकास जायसवाल
कोण्डागांव :	सुरेश पाटले
नारायणपुर :	नरेन्द्र देवांगन
जगदलपुर :	हेमंत कश्यप
धमतरी :	जियाऊल हुसैनी
बालोद :	सलीम चौहान
बलौदाबाजार :	संतोष यादव
तिल्दा-नेवरा :	दिलीप वर्मा
बोड़ला :	नवलकिशोर श्रीवास्तव
अंबिकापुर :	धनंजय दुबे
मनेन्द्रगढ़ :	मनप्रीत सिंह साहनी
रामानुजगंज :	विकास केसरी
वाडफनगर :	प्रदीप जायसवाल
दल्लीराजहरा :	झुनमुन गुप्ता
गुंडरदेही :	रमेश चांडक
पाटन :	उमाशंकर वर्मा
उतई :	सतीश पारख
बलरामपुर :	नितेश श्रीवास्तव
दंतेवाड़ा :	देवकरण बुरड
सरगुजा/जशपुर :	अनिल मानिकपुरी

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय

ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
भिलाई कार्यालय : जी.ई. रोड, कोसानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
संपर्क : 99261 80287, 88895 70726

प्रसार व विज्ञापन विभाग

पत्रिका की सदस्यता व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
भूपेन्द्र वर्मा-8889570726, गजेन्द्र-7999139990,
दिनेश कुमार-6264374105

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए भारत प्रिंटरर्स,
विधानसभा भवन के पास, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम
तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, संपादक - लखन लाल

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामाग्री की नकल प्रतिबंधित है.
सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.



12

आवरण - कथा

सत्ता बदली, पद छूटा, पर कायम रहा...

छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री का पद प्रशासनिक गंभीरता और संवैधानिक गरिमा से जुड़ा होता है, लेकिन 2018 से 2023 के दौरान भूपेश बघेल ने इस पद को एक नया मानवीय और लोकव्यापी रूप दिया. विधानसभा में आक्रामक तेवर और मंच पर तीखे तीरों के बीच जब वे गेंड़ी चढ़ते, भौंरा चलाते और ठेठ छत्तीसगढ़ी में बतियाते, तो सत्ता की औपचारिक दूरी...



24

जिसके लिए उजड़े 40 से अधिक गांव, क्या उसके ...

देश की औद्योगिक रीढ़ और 'मिनी इंडिया' के रूप में पहचाने जाने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के 47 हजार करोड़ रुपये...

निवेश की नई उड़ान से समृद्धि के पथ...

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है परंतु सत्ता पक्ष को जनता की अभिव्यक्ति से अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आता है. लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है....



34

06 टकराव : जनप्रतिनिधि बनाम नौकरशाह की लड़ाई...

28 चुनावी बिगुल : जल्द बजेगा नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल...

30 विशेष लेख : महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय...

38 याचिका : खतरनाक है, अपराध का राजनीतिकरण...

48 व्यंग्य : कमजोर विपक्ष की मजबूती...



लखन लाल

छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि में 'जेन जी' का नया तेवर

छत्तीसगढ़ की 'जेन जी' केवल शिकायतें दर्ज नहीं करा रही है, बल्कि वह राज्य के विकास के एजेंडे को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। यह आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि राज्य का युवा अपने अधिकारों, पर्यावरण और रोजगार के प्रति सतर्क और जागरूक है। यदि सत्ता और समाज ने इस नई चेतना को समझकर इसके साथ संवाद स्थापित नहीं किया, तो यह असंतोष आने वाले समय में राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदलने का सामर्थ्य रखता है।

छत्तीसगढ़ का 'जेन जी' आंदोलन देश के अन्य हिस्सों से थोड़ा अलग और अनूठा है। यह केवल मेट्रो शहरों की चकाचौंध या सोशल मीडिया ट्रेंड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें राज्य की धरातली समस्याओं से गहराई से जुड़ी हैं :

राज्य लोक सेवा आयोग (CGPSC) में हुई धांधलियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं का गुस्सा सड़कों से लेकर डिजिटल स्पेस तक दिखाई दिया है। कोर्ट के सख्त रुख और केंद्रीय एजेंसियों की जांच के बीच युवाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी मेहनत का हक किसी भी कीमत पर छिनने नहीं देंगे।

छत्तीसगढ़ के समृद्ध जंगलों (जैसे हसदेव अरण्य) और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए 'जेन जी' युवा बिना किसी राजनीतिक झंडे के सोशल मीडिया अभियानों और जमीनी स्तर पर एकजुट हो रहे हैं।

रील्स, मीम्स और हैशटैग अभियानों के जरिए जटिल से जटिल नीतिगत फैसलों और अनियमितताओं को सरल भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत करना इनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था हमेशा से जातिगत आंकड़ों, वादों और रैलियों पर आधारित रही है। इसके विपरीत, 'जेन जी' आंदोलन किसी स्थापित चेहरा या राजनीतिक दल के मोहताज नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ में युवाओं का यह नया उभार शासन और प्रशासन के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब पुरानी कार्यशैली से काम नहीं चलेगा। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात आती है, तो युवा किसी भी प्रकार के राजनीतिक आश्वासनों के बजाय त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।

सड़कों पर उतरते युवाओं और लगातार बदलते डिजिटल परिदृश्य को केवल "क्षणिक आक्रोश" मानकर खारिज करना राज्य के नीति-निर्माताओं के लिए भूल साबित हो सकती है।



09 अगस्त 2026

विश्व आदिवासी दिवस

की समस्त भाईयों एवं बहनों को

हार्दिक शुभकामनाएं



हेमंत नेताम



नेहरू सिंह परिहार



चन्द्रभान सिंह ठाकुर



रूखमणी ठाकुर



चन्द्रकला तारम



दिनेश्वरी भुआर्य



उमा सिंह



अश्लेष मरावी



पल्लवी नेताम





पूर्णचंद्र 'कोको' पाढ़ी



अनूप वर्मा

कोको और अनूप की जोड़ी ने संगठन को दी नई धार

छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा संगठन 'युवा कांग्रेस' की सक्रियता और प्रभाव के पीछे जमीनी संघर्ष और आधुनिक डिजिटल रणनीति का बेहतर संतुलन देखने को मिल रहा है। इस सांगठनिक मजबूती का मुख्य श्रेय भानुप्रतापपुर के जमीनी नेता पूर्णचंद्र "कोको" पाढ़ी और दुर्ग के डिजिटल रणनीतिकार अनूप वर्मा की नेतृत्व क्षमता को जाता है।

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

महासचिव भी नियुक्त किया गया।

बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के 'कोको' ने बनाई राष्ट्रीय पहचान

कांकर जिले के भानुप्रतापपुर से आने वाले पूर्णचंद्र "कोको" पाढ़ी ने किसी राजनीतिक घराने का सहारा लिए बिना महज 16 वर्ष की उम्र में छाल राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की थी। एनएसयूआई (NSUI) के शहर अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक, विधानसभा और लोकसभा स्तर पर निर्वाचित होते हुए उन्होंने ओडिशा युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में लगभग 5 वर्षों तक संगठन को संभाला।

वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और उनके आक्रामक प्रदर्शनों को देखते हुए 30 जून 2019 को पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जमीनी स्तर पर उनकी कार्यकुशलता के बल पर उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) का राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय

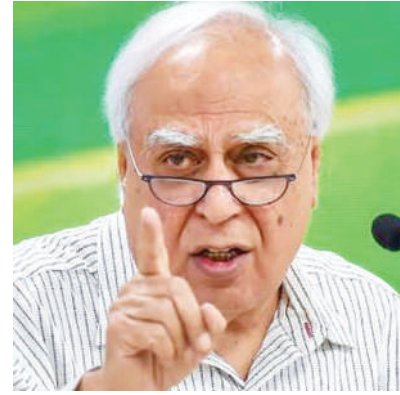
बूथ स्तर तक डिजिटल क्रांति

वहीं दूसरी ओर दुर्ग जिले से संबंध रखने वाले अनूप वर्मा ने आधुनिक दौर में संगठन को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया सेल के प्रदेश चेयरमैन रहते हुए उन्होंने प्रदेशभर में बूथ स्तर तक डिजिटल वालंटियर्स और सोशल मीडिया वॉरियर्स का नेटवर्क खड़ा किया।

पार्टी की नीतियों, जनकल्याणकारी योजनाओं और विपक्ष के हमलों का डिजिटल जवाब देने में उनके सांगठनिक कौशल को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पदोन्नत कर छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। वर्तमान में वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रणनीतियों और हितग्राही संपर्क अभियानों के प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे हैं।

मंशा आरक्षण की नहीं, संविधान बदलने की है

बारह साल में सिर्फ बीजेपी का हुआ विकास !



कपिल सिब्बल

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

निर्दलीय राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए चार प्रमुख मुद्दों 'दिमागी नक्सली', महिला आरक्षण, वोटर लिस्ट सुधार और 'नेशन फर्स्ट' पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चला रही है. महिला आरक्षण में हो रही देरी, गिरती अर्थव्यवस्था, युवाओं में बेरोजगारी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को रेखांकित करते हुए सिब्बल ने कहा कि पिछले 12 सालों में विकास केवल कागज़ों और राजनीतिक फायदों तक सीमित रहा है, जबकि देश का असली विकास अब भी अधूरा है. 'विकसित भारत' और 'नेशन फर्स्ट' के दिए गए संदेश पर उन्होंने सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत उजागर की. सिब्बल ने कहा कि जब देश का युवा 29% बेरोजगारी दर से जूझ रहा हो और 80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर निर्भर हों, तब 'ग्लोबल सप्लायर' बनने के सपने बेमानी लगते हैं. स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और एआई (AI) के दावों की पोल खोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष, महिला आरक्षण सहित हर जनहित के मुद्दे पर साथ खड़ा है, लेकिन सरकार की मंशा देश को जोड़ने की नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ और संवैधानिक ढांचे को बदलने की है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लाल किले के संबोधन पर
विपक्षी नेता का तीखा प्रहार

सरकारी, सामाजिक और
पैदाइशी तानाशाह

स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी
के बयानों पर कपिल सिब्बल
का करारा पलटवार!

के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर तीखा हमला बोला है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश में तीन तरह के तानाशाह—सरकारी, सामाजिक और पैदाइशी हावी हैं, जिन्हें अब देश की जनता और युवा समझ चुके हैं.

सिब्बल ने कहा कि 'दिमागी नक्सली' जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन युवाओं, बुद्धिजीवियों और शिक्षाविदों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जो सरकार की नीतियों से असहमत हैं.

महिला आरक्षण बिल पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि नीयत साफ है, तो इसी सत्र में 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि डीलिटिमेशन (परिसीमन) के नाम पर चुनावी क्षेत्रों में हेरफेर करने की योजना बनाई जा रही है.

विकास के दावों की आलोचना करते हुए सिब्बल ने कहा कि

पिछले 12 वर्षों में जमीनी स्तर पर रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में ठोस सुधार नहीं हुआ, बल्कि स्मार्ट सिटी और नए इन्फ्रास्ट्रक्चर के दावे पहली ही बारिश में धुल जाते हैं. उन्होंने ग्रीन इकॉनामी, एआई (AI) और स्किल इंडिया की योजनाओं को भी बिना ठोस तैयारी के दिखाए गए सपने करार दिया. इसके साथ ही, टीएमसी सांसद महुआ मोइता से जुड़े हालिया मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में महिलाओं के सम्मान को लेकर बड़ा अंतर है.



नरेन्द्र मोदी

जनप्रतिनिधि बनाम नौकरशाह की लड़ाई

छत्तीसगढ़ में सत्ता और नौकरशाही के बीच बढ़ते कथित टकराव ने अब सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और IAS अमित कटारिया के बीच पत्रों के जवाब और कथित फोन बातचीत को लेकर विवाद लोकसभा तक पहुंचा है, तो दूसरी तरफ दुर्ग सांसद विजय बघेल और भिलाई-चरोदा निगम आयुक्त डीएस राजपूत के बीच संवाद और प्रशासनिक सहयोग का मामला भी विशेषाधिकार हनन की शिकायत तक पहुंच गया है। दो सांसद, दो अधिकारी और दोनों मामलों में एक जैसा सवाल क्या जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच संवाद की मर्यादा और समन्वय की कड़ी कमजोर पड़ रही है?

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

आखिर टकराव की वजह क्या है?

बात 20 मई 2026 की है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र और जनहित से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को कई पत्र और स्मरण पत्र भेजे, लेकिन लंबे समय तक अपेक्षित जवाब नहीं मिला। इसी सिलसिले में उन्होंने फोन पर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव स्तर तक पहुंचा और कथित तौर पर बातचीत हुई। इसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच स्थिति बिगड़ने का दावा किया जा रहा है।

‘जो करना है कर लो’ ने बढ़ाया विवाद

श्री अग्रवाल की शिकायत के अनुसार, फोन पर बातचीत के दौरान अधिकारी का रवैया कथित तौर पर रूखा और असम्मानजनक था। सांसद का आरोप है कि बातचीत के दौरान उन्हें “जो करना है कर लो” जैसा जवाब दिया गया।

हालांकि, इस कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और अमित कटारिया की ओर से इस पूरे आरोप पर

बृजमोहन अग्रवाल, सांसद, रायपुर

“फोन पर बातचीत के दौरान अधिकारी का रवैया अपमानजनक था, जो करना है कर लो जैसा शब्द बोला ”



विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। इसलिए इस कथन को फिलहाल सांसद द्वारा लगाए गए आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

सांसद ने क्यों उठाया विशेषाधिकार का मुद्दा?

बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि वे रायपुर के निर्वाचित लोकसभा सांसद हैं और जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासन से संवाद करना उनका लोकतांत्रिक दायित्व है। उनके अनुसार, पत्रों का जवाब न मिलना और कथित तौर पर फोन पर इस तरह का व्यवहार करना सिर्फ व्यक्तिगत असहमति का विषय नहीं, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि और संसदीय व्यवस्था के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है।

इसी आधार पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत/नोटिस दिया। इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से संबंधित स्तर पर मामले की तथ्यात्मक जानकारी मांगे जाने की रिपोर्ट सामने आई है।

असली टकराव ‘अधिकार’ का है या ‘कामकाज’ का?

सांसद का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद और समन्वय रखना चाहिए। दूसरी

तरफ नौकरशाहों के स्तर पर अधिकारियों की भूमिका नियमों, प्रक्रियाओं और विभागीय अधिकार-सीमा के भीतर काम करने की होती है।

यानी विवाद केवल एक फोन कॉल तक सीमित नहीं दिखता। इसके पीछे जनप्रतिनिधि की अपेक्षा बनाम प्रशासनिक प्रक्रिया, राजनीतिक हस्तक्षेप की सीमा, और अधिकारी की जवाबदेही जैसे बड़े सवाल भी जुड़े हुए हैं।

विवाद में 108 एंबुलेंस का मुद्दा भी जुड़ा

मामले ने तब और राजनीतिक रंग ले लिया जब स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर 108 एंबुलेंस सेवा और उससे जुड़ी टेंडर प्रक्रिया, को लेकर भी सवाल उठाए गए। अगस्त में पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। हालांकि, किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार का निष्कर्ष जांच के बिना निकालना उचित नहीं होगा।

भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

“राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन निर्वाचित सांसद के साथ प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए”



करता है।

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद में अंतिम रूप से गलती किसकी थी। लोकसभा स्तर पर मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट और आगे होने वाली जांच से ही तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी।

विपक्ष से भी मिला बृजमोहन को समर्थन

दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में बयान दिया। उनका कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन निर्वाचित सांसद के साथ प्रशासनिक अधिकारी का व्यवहार मर्यादित होना चाहिए।

सांसद श्री अग्रवाल लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रभावशाली नेता हैं और वर्तमान में रायपुर से लोकसभा सांसद हैं। वहीं अमित कटारिया 2004 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। ऐसे में दोनों के बीच विवाद का सार्वजनिक होना महज व्यक्तिगत मतभेद नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन के बीच समन्वय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े

बघेल-राजपूत में टकराव की वजह क्या?

छत्तीसगढ़ में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अफसरशाहों के बीच कथित टकराव का एक और मामला सामने आया है। दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने भिलाई-चरोदा नगर निगम के आयुक्त डीएस राजपूत के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। सांसद का आरोप है कि जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला और उनके फोन का भी अपेक्षित जवाब नहीं दिया गया।

आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

मामले के केंद्र में सांसद और निगम आयुक्त के बीच संपर्क और संवाद को लेकर पैदा हुआ विवाद बताया जा रहा है। विजय बघेल का कहना है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी और सहयोग मांगा था। आरोप है कि भिलाई-चरोदा निगम आयुक्त डीएस राजपूत ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया और जरूरी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई। सांसद ने इसे महज व्यक्तिगत असहमति नहीं, बल्कि एक निर्वाचित सांसद के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा विषय माना और लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष मामला उठाया।

सिर्फ फोन नहीं उठाना ही क्या विवाद की वजह है?

पूरे मामले को सिर्फ फोन कॉल तक सीमित देखना शायद सही तस्वीर नहीं होगी।

विजय बघेल, सांसद, दुर्ग

“अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों पर मैंने निगम आयुक्त से जानकारी मांगी थी, पर न फोन का जवाब दिया और न ही जानकारी उपलब्ध करायी।”



सांसद की शिकायत में मुख्य सवाल यह है कि क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा मांगी गई जनहित की जानकारी और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया गया या नहीं?

श्री बघेल का आरोप है कि उन्हें प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. दूसरी ओर, उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों में निगम आयुक्त की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है.

इसलिए फिलहाल यह कहना उचित नहीं होगा कि अधिकारी ने जानबूझकर सांसद की उपेक्षा की. यह तथ्य जांच और संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद ही स्पष्ट होगा.

मामला लोकसभा तक क्यों पहुंचा?

विजय बघेल ने इसे विशेषाधिकार हनन का मामला मानते हुए लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की. रिपोर्टों के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने राज्य शासन और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

यानी अब विवाद केवल नगर निगम और सांसद के बीच का प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है. इसकी जांच संसदीय स्तर पर भी हो रही है.



भिलाई-चरोदा निगम में पहले से उठ रहे थे सवाल

इस विवाद के बीच भिलाई-चरोदा नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय स्तर पर भी सवाल उठते रहे हैं. जून 2026 में भाजपा ने निगम में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था.

हालांकि, इन आरोपों को सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता. किसी भी कथित अनियमितता या भ्रष्टाचार पर अंतिम निष्कर्ष जांच या सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही निकाला जा सकता है.

बृजमोहन अग्रवाल के मामले से जुड़ रहा है मामला

विजय बघेल की शिकायत ऐसे समय सामने आई है जब रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा में उठा चुके हैं.

इस वजह से छत्तीसगढ़ में यह बहस तेज हो गई है कि क्या राज्य में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच संवाद एवं समन्वय में कमी बढ़ रही है.

विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार के भीतर प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक अंतर्कलह से जोड़कर देख रहा है, जबकि भाजपा नेताओं का जोर इस बात पर है कि अधिकारियों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मर्यादित और जवाबदेह संवाद रखना चाहिए.

असली सवाल क्या है ?

इस पूरे विवाद में तीन सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं :

पहला : क्या सांसद ने जिन जनहित के मामलों में जानकारी मांगी थी, उन पर निगम प्रशासन ने समय पर जवाब दिया?

दूसरा : क्या सांसद के फोन का जवाब न देना प्रशासनिक व्यस्तता/प्रक्रिया का हिस्सा था या जानबूझकर संवाद से बचने का मामला?

तीसरा : क्या किसी अधिकारी का व्यवहार इतना गंभीर था कि उसे संसदीय विशेषाधिकार के प्रश्न से जोड़ा जाए?

इन सवालों का जवाब संबंधित अधिकारियों और राज्य शासन की रिपोर्ट के बाद ज्यादा स्पष्ट होगा.



श्री मल्लिका अर्जुन स्वर्गो



श्री राहुल गांधी जी



श्रीमती प्रियंका गांधी जी



श्री दीपक बैज जी
अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी



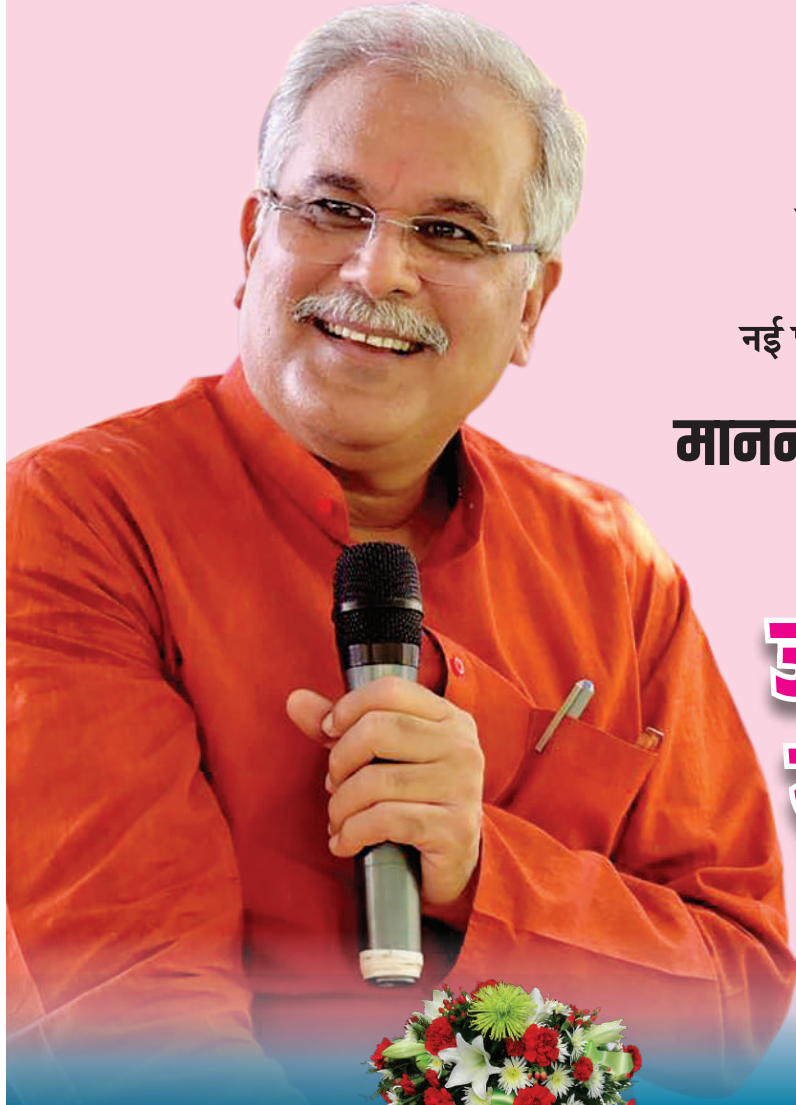
श्री चरणदास महंत जी
नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा



छत्तीसगढ़ी संस्कृति, माटी
और परंपराओं को
नई पहचान देने वाले जनप्रिय नेता

माननीय श्री भूपेश बघेल जी
को

**जन्मदिन
मुबारक**



कुंवर सिंह निषाद
विधायक, गुण्डरदेही
जिला बालोद (छ.ग.)



15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की प्रदेशवासियों को

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं



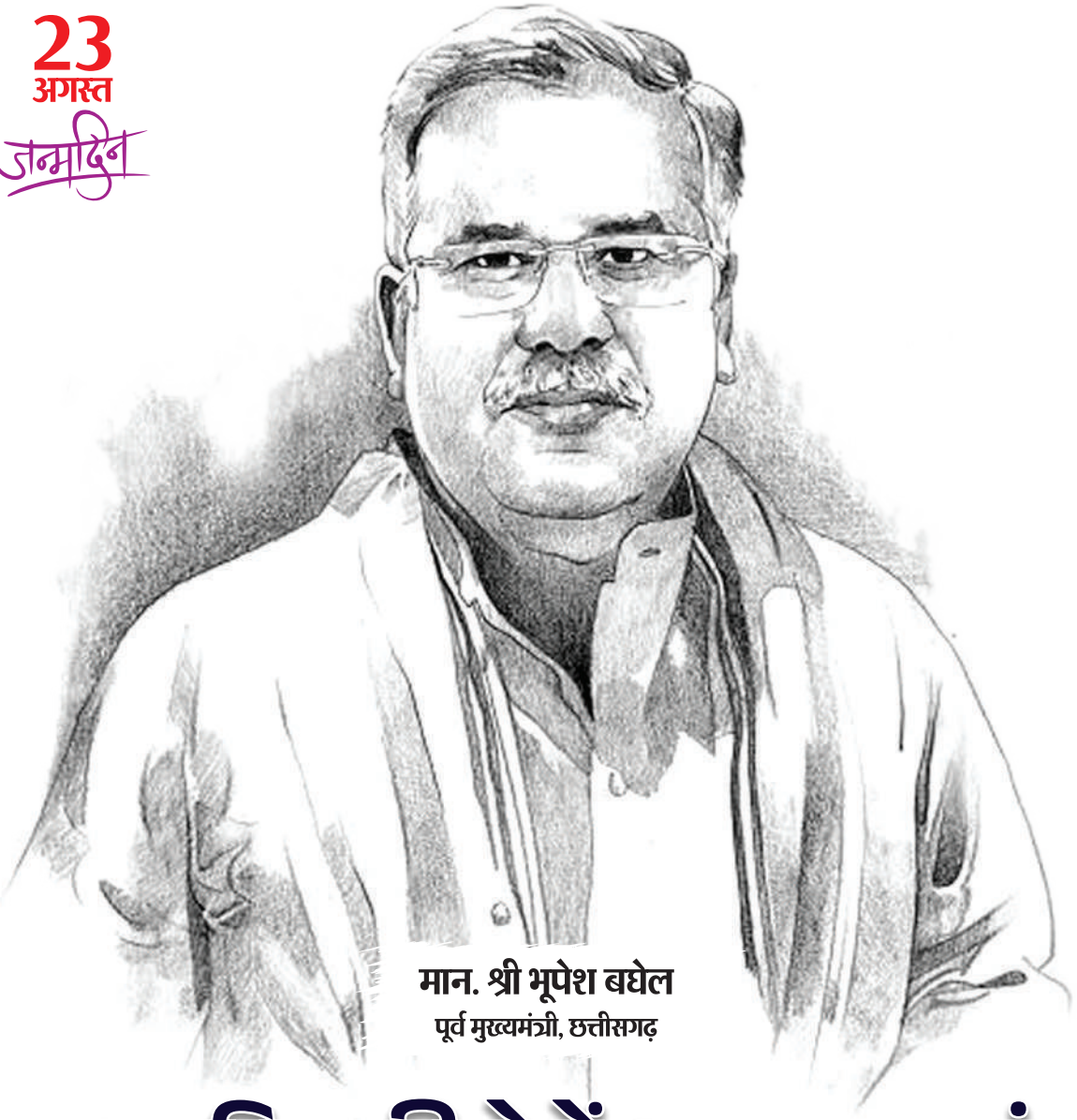
सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद का वितरण

समर्थन मूल्य का उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराकर पीडीएस के लिए नान और एफसीआई को सौंपना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला- दुर्ग (छ.ग.)

23
अगस्त
जन्मदिन



मान. श्री भूपेश बघेल
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं

कामयाबी और उत्तम स्वास्थ्य हमेशा आपके साथ रहे...

आई. एस. मनु

“कका अभी जिंदा है”



सत्ता बदली, पद छूटा, पर कायम रही कका की मकबूलियत

जनता के बीच बनाया
भावनात्मक रिश्ता

जानिए कैसे एक नारा भूपेश बघेल
की अमिट पहचान बन गयी!

गेंड़ी, भौंरा, तीजा, पोरा
और माटी की महक

छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री का पद प्रशासनिक गंभीरता और संवैधानिक गरिमा से जुड़ा होता है, लेकिन 2018 से 2023 के दौरान भूपेश बघेल ने इस पद को एक नया मानवीय और लोकव्यापी रूप दिया. विधानसभा में आक्रामक तेवर और मंच पर तीखे तीरों के बीच जब वे गेंड़ी चढ़ते, भौंरा चलाते और ठेठ छत्तीसगढ़ी में बतियाते, तो सत्ता की औपचारिक दूरी मिट जाती. “कका अभी जिंदा है” सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास का वह प्रतीक बना, जिसने पद जाने के बाद भी उन्हें प्रदेश की जनता के दिल और माटी की महक से जोड़े रखा है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

राजनीति में अक्सर सत्ता जाते ही पहचान धुंधली पड़ने लगती है, लेकिन भूपेश बघेल के ‘कका’ वाले संबोधन ने इस धारणा को बदल दिया है. हरेली, तीजा और पोरा जैसे लोकपर्वों को मुख्यमंत्री निवास के आंगन तक लाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जो सम्मान दिया, उसने आम जनता के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता कायम किया. सोशल मीडिया से लेकर गांव के चौपालों तक, एक किसान पुत्र की सहजता और जमीनी पकड़ ही उनकी असली ब्रांड पहचान बनी एक ऐसा रिश्ता जो कुर्सी रहने या न रहने का मोहताज नहीं है.

सियासत के मंच पर आक्रामक तेवर, जनता के बीच ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज.. भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के पांच वर्षों में एक ऐसी राजनीतिक छवि गढ़ी, जिसमें सत्ता की औपचारिकता से ज्यादा माटी की महक और रिश्तों की आत्मीयता दिखाई दी. छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक गरिमा, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और सत्ता की गंभीरता से जुड़ा होता है. लेकिन वर्ष 2018 से 2023 के बीच इस पद पर बैठे भूपेश बघेल ने इस औपचारिक छवि के साथ एक ऐसा मानवीय रिश्ता भी बनाया, जिसने उन्हें प्रदेश की जनता के बीच एक अलग पहचान दी. यह पहचान थी, “कका” की. ‘कका’ यानी परिवार का वह बुजुर्ग, जिसके साथ औपचारिकता कम और अपनापन अधिक होता है. जिसके सामने अपनी बात कहने में झिझक नहीं होती. जो जरूरत पड़ने पर डांट भी सकता है और मुश्किल समय में साथ भी खड़ा दिखाई देता है. भूपेश बघेल के राजनीतिक व्यक्तित्व में यही समन्वय दिखाई देता रहा, एक ओर तीखे राजनीतिक तेवर, दूसरी ओर गांव के आंगन जैसी सहजता. एक ओर विधानसभा और चुनावी मंच पर आक्रामक नेता, दूसरी ओर गेंड़ी पर चढ़ता, भौंरा चलाता और छत्तीसगढ़ी में बतियाता ‘कका’.

‘कका अभी जिंदा है’ नारा जो पहचान बन गया

राजनीति में नारे अक्सर चुनाव तक सीमित रहते हैं, लेकिन कुछ नारे नेता की सार्वजनिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं. भूपेश बघेल का वाक्य, “कका अभी जिंदा है”, ऐसा ही एक राजनीतिक वाक्य बन गया. इस वाक्य में केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि राजनीतिक चुनौती का जवाब देने का अंदाज भी था. जब

राजनीतिक विरोधी उनकी सरकार या उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते, तब समर्थकों के बीच यह वाक्य एक तरह के राजनीतिक संदेश में बदल जाता. ‘कका अभी जिंदा है’ का अर्थ केवल इतना नहीं था कि नेता अभी सक्रिय है. इसके भीतर यह संदेश भी था कि राजनीतिक संघर्ष में उन्हें आसानी से हाशिए पर नहीं धकेला जा सकता. यही कारण है कि यह वाक्य धीरे-धीरे एक राजनीतिक संवाद से आगे बढ़कर भूपेश बघेल की ब्रांड पहचान का हिस्सा बन गया.

‘कका’ की छवि और सोशल मीडिया

भूपेश बघेल की ‘कका’ वाली छवि को सोशल मीडिया ने भी व्यापक बनाया. उनके गेंड़ी चढ़ने, भौंरा चलाने, छत्तीसगढ़ी में संवाद करने और लोक पर्वों में शामिल होने की तस्वीरें और वीडियो तेजी से प्रसारित हुए. इससे उनकी छवि केवल राजनीतिक समर्थकों तक सीमित नहीं रही. एक ऐसी डिजिटल पीढ़ी, जो परंपरागत राजनीतिक भाषा से दूरी रखती है, उसके बीच भी ‘कका’ एक पहचान बन गया. राजनीतिक ब्रांडिंग की भाषा में यह एक दिलचस्प प्रयोग था. एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को पारिवारिक संबोधन के जरिए जनता के करीब लाना. ‘कका’ शब्द में छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना की आत्मीयता छिपी है. यहां रिश्ते केवल रक्त संबंधों से नहीं, बल्कि व्यवहार और अपनत्व से भी बनते हैं. लेकिन इस पहचान को केवल प्रचार की देन मानना भी पर्याप्त नहीं होगा. इसके पीछे वर्षों का ग्रामीण जुड़ाव, स्थानीय भाषा पर पकड़, लोकजीवन की समझ और जनता के बीच सहज उपस्थिति थी. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने लिए ऐसी भाषा चुनी, जिसमें ‘माननीय मुख्यमंत्री’ की दूरी कम और ‘कका’ की निकटता अधिक थी.

मुख्यमंत्री, लेकिन बातचीत में गांव का आदमी

भूपेश बघेल की लोकप्रियता का एक कारण उनकी संवाद शैली भी रही. मुख्यमंत्री पद की औपचारिकता के बावजूद वे आम लोगों के बीच बातचीत में अक्सर छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय मुहावरों का इस्तेमाल करते थे. यह शैली भाषणों तक सीमित नहीं रही. जनसभाओं, ग्रामीण कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में उनका स्थानीय अंदाज दिखाई देता रहा. उनका यह

अंदाज ग्रामीण समाज के लिए परिचित था. शायद इसलिए 'कका' का संबोधन धीरे-धीरे राजनीतिक नारे से आगे बढ़कर आत्मीयता का प्रतीक बन गया. छत्तीसगढ़ में हरेली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी सांस्कृतिक परंपरा है. मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल का हरेली के अवसर पर गेंड़ी चढ़ाना, भौंरा चलाना और पारंपरिक गतिविधियों में हिस्सा लेना उनकी सार्वजनिक छवि का महत्वपूर्ण हिस्सा बना. एक मुख्यमंत्री जब राजकीय प्रोटोकॉल से बाहर निकलकर ग्रामीण संस्कृति की सहज गतिविधियों में हिस्सा लेता है, तो वह जनता को केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं देता; वह अपनी सामाजिक जड़ों का भी प्रदर्शन करता है. भूपेश बघेल के लिए यह संदेश स्पष्ट था, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी पहचान किसान परिवार से निकले उस व्यक्ति की है, जिसकी जड़ें गांव की मिट्टी में हैं. यही दृश्य उनकी 'कका' वाली छवि को मजबूत करते रहे. तीजा-पोरा जैसे अवसरों पर मुख्यमंत्री निवास में महिलाओं और आम लोगों की भागीदारी ने भी भूपेश बघेल की सार्वजनिक छवि को एक अलग आयाम दिया.. मुख्यमंत्री निवास जैसी सत्ता की जगह को आम जनता के सांस्कृतिक जीवन के करीब लाने की कोशिश दिखाई दी.

सत्ता गई लेकिन संबोधन वही !

2023 में छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ. मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, लेकिन 'कका' का संबोधन खत्म नहीं हुआ. यही किसी राजनीतिक छवि की वास्तविक परीक्षा होती है. पद समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि जनता के बीच बनाया गया भावनात्मक रिश्ता कायम रहता है, तो राजनीतिक पहचान भी बनी रहती है. भूपेश के मामले में 'कका' इसी स्थायित्व का प्रतीक दिखाई देता है. उनके समर्थकों के लिए यह आज भी केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान है. उनकी सार्वजनिक शैली में ग्रामीण जीवन से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल इसी संदर्भ में देखा जा सकता है. गेंड़ी, भौंरा, हरेली, तीजा, पोरा और छत्तीसगढ़ी भाषा.. ये सभी प्रतीक उनकी राजनीति में बार-बार दिखाई दिए. इन प्रतीकों ने यह धारणा मजबूत की कि वे छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति को केवल चुनावी मंच पर याद करने वाले नेता नहीं, बल्कि उसे सार्वजनिक जीवन में सम्मान देने वाले राजनेता हैं.

जमीनी संघर्ष और छत्तीसगढ़िया आत्मविश्वास का व्यक्तित्व

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में रचा इतिहास



छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूपेश बघेल का व्यक्तित्व एक ऐसे जननेता के रूप में उभरता है, जिसकी पहचान केवल पद और सत्ता से नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी, बोली और लोकजीवन से गहरे जुड़ाव के कारण बनी है. एक किसान परिवार की पृष्ठभूमि से निकलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद तक पहुँचना उनके राजनीतिक संघर्ष की कहानी तो है ही, साथ ही यह उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को भी सामने लाता है, जिनमें जमीनी जुड़ाव, स्पष्टवादिता, राजनीतिक दृढ़ता और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति आत्मविश्वास दिखाई देता है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भूपेश बघेल का सार्वजनिक जीवन लंबे राजनीतिक संघर्ष से निर्मित हुआ है. अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहते हुए उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियाँ निभाई और धीरे-धीरे देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. उनके व्यक्तित्व की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है, राजनीति को जमीन से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति. वे गांव, किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय संस्कृति

को केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ के सामाजिक जीवन का मूल आधार भी मानते हैं।

सहज और सरल व्यक्तित्व की अमिट छाप

उनकी सार्वजनिक छवि में एक खास तरह की सहजता दिखाई देती है। वे पारंपरिक अर्थों में अत्यधिक औपचारिक राजनीतिक व्यक्तित्व की बजाय आम लोगों के बीच घुलने-मिलने वाले नेता के रूप में अधिक दिखाई देते हैं। बातचीत में स्थानीय शब्दों और छत्तीसगढ़ी संदर्भों का इस्तेमाल उनकी शैली का हिस्सा रहा है। यही सहजता उन्हें ग्रामीण और सामान्य जनमानस के करीब ले जाती है।

के रूप में उनका कार्यकाल उस समय आया जब पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने और राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाने की बड़ी चुनौती थी।

उनकी नेतृत्व शैली में आक्रामक राजनीतिक तेवर भी दिखाई देते हैं। वे अपने राजनीतिक विरोधियों पर सीधे और तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थकों के लिए यह स्पष्टवादिता और निर्भीकता है, जबकि आलोचक कभी-कभी इसे आवश्यकता से अधिक आक्रामक राजनीतिक शैली के रूप में देखते हैं। यही विरोधाभास उनके व्यक्तित्व को रोचक बनाता है। वे ऐसे नेता नहीं हैं जिनकी राजनीति हर किसी को समान रूप से स्वीकार्य लगे; बल्कि उनका व्यक्तित्व समर्थन और विरोध, दोनों को बड़ी गंभीरता के साथ



उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष केवल व्यवहार तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीति में भी स्थानीय समाज और संस्कृति को विशेष महत्व मिला। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, तीज-त्योहारों, लोक कलाओं और स्थानीय प्रतीकों को सार्वजनिक विमर्श में अपेक्षाकृत अधिक प्रमुखता मिली। इससे उनकी राजनीतिक शैली में एक प्रकार का छत्तीसगढ़ी आत्मविश्वास दिखाई दिया। ऐसा आत्मविश्वास जो अपनी क्षेत्रीय पहचान को संकोच के बजाय गौरव के साथ प्रस्तुत करता है।

सफलता की पीछे संघर्षों की दास्तान

भूपेश बघेल के राजनीतिक व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके संघर्षशील पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक चुनौतियों और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के दौर से गुजरते हुए उन्होंने अपनी जगह बनाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

नरवा, गरवा, घुरुवा, बारी की
बात करने वाले पहले मुख्यमंत्री

गाँव-किसान, ग्रामीण
अर्थव्यवस्था के कुशल चितरे

संघर्षों में पले-बढ़े और खेले
गाँव-देहात में

आकर्षित करता है।

गाँव-किसान एक बेटा और देहाती जीवन से जुड़े

भूपेश बघेल की राजनीतिक सोच में किसान और ग्रामीण समाज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष उनकी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसान की आर्थिक स्थिति, ग्रामीण

रोजगार और स्थानीय बाजार की भूमिका को लेकर उनकी राजनीति ने एक विशिष्ट दिशा ग्रहण की।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में किसानों से जुड़े निर्णयों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजनाओं को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा गया। धान खरीदी, किसानों को आर्थिक सहायता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े कार्यक्रमों ने उनकी सरकार की पहचान बनाने में भूमिका निभाई। इन नीतियों के प्रभाव और उनके क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक मतभेद और बहस अपनी जगह हैं,

लेकिन यह निर्विवाद है कि उन्होंने किसान और गांव को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया।

छत्तीसगढ़ी अस्मिता, व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण आधार

भूपेश बघेल के व्यक्तित्व की सबसे विशिष्ट पहचान शायद छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के प्रति उनका आग्रह है। छत्तीसगढ़ी भाषा, लोकपर्व, लोक नृत्य, लोकगीत और ग्रामीण परंपराओं को उन्होंने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रमुखता दी। हरेली, तीजा, पोला जैसे पारंपरिक पर्वों को व्यापक सार्वजनिक पहचान दिलाने की कोशिशों ने उनकी राजनीति को सांस्कृतिक आयाम भी दिया। उनके लिए छत्तीसगढ़िया पहचान केवल सांस्कृतिक प्रतीकों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इसे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी देखने की कोशिश की। स्थानीय उत्पाद, स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की नीति इसी सोच का हिस्सा मानी जा सकती है। इस दृष्टि से उनका व्यक्तित्व उस राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें विकास की चर्चा के साथ यह सवाल भी जुड़ा है कि विकास का मॉडल स्थानीय समाज और संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है।

सत्ता से आगे भी बनी राजनीतिक पहचान

मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनकी राजनीतिक सक्रियता और सार्वजनिक उपस्थिति बनी रही। इससे यह संकेत मिलता है कि उनकी पहचान केवल मुख्यमंत्री पद से निर्मित नहीं हुई थी। लंबे समय तक संगठन और चुनावी राजनीति में सक्रिय रहने के कारण उनका अपना एक राजनीतिक आधार और व्यक्तित्व विकसित हुआ। एक राजनेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि वे अपनी राजनीति को केवल राजधानी के राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रखते। उनकी भाषा और राजनीतिक प्रतीकों में अक्सर गांव, किसान और स्थानीय समाज दिखाई देता है। यही कारण है कि वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक

विशिष्ट पहचान रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं।

व्यापक राजनीतिक दृष्टि एवं आक्रामक शैली

भूपेश बघेल का व्यक्तित्व एकरेखीय नहीं है। उन्हें केवल किसान नेता, केवल कांग्रेस नेता या केवल छत्तीसगढ़ी अस्मिता के प्रतीक के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होगा। वे एक ऐसे राजनेता हैं, जिनमें सहजता और आक्रामकता, परंपरा और राजनीतिक आधुनिकता, स्थानीयता और व्यापक राजनीतिक दृष्टि, कई स्तर एक साथ दिखाई देते हैं। उनकी राजनीति की उपलब्धियों का मूल्यांकन करते समय नीतियों के परिणाम, प्रशासनिक प्रदर्शन और राजनीतिक निर्णयों पर अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करते समय यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति की भाषा और प्रतीकों पर अपना प्रभाव छोड़ा है। उनकी राजनीतिक यात्रा अंततः उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी क्षेत्रीय पहचान को अपनी राजनीतिक शक्ति में बदला। मिट्टी से जुड़ी भाषा, ग्रामीण समाज के प्रति आत्मीयता, संघर्ष करने का स्वभाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पीछे न हटने की प्रवृत्ति, ये सभी तत्व मिलकर उनके व्यक्तित्व को आकार देते हैं।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले समय में उनके योगदान का मूल्यांकन अलग-अलग कसौटियों पर किया जाएगा। इतिहास उनके शासन की उपलब्धियों और कमियों का हिसाब लगाएगा, राजनीतिक विश्लेषक उनकी रणनीतियों की समीक्षा करेंगे और जनता अपने अनुभवों के आधार पर अपना निष्कर्ष देगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है, जिसे केवल किसी पद के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता।

उनका व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में स्थानीयता, लोक संस्कृति और जमीनी जुड़ाव आज भी किसी नेता की राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। भूपेश बघेल की कहानी इसलिए केवल एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं, बल्कि उस राजनीतिक व्यक्तित्व की कहानी भी है जिसने अपनी मिट्टी की भाषा और पहचान को सत्ता के विमर्श का हिस्सा बनाया।



आत्मविश्वास और ठोस राजनीतिक धरातल की बुनियाद

भूपेश बघेल की एक अन्य विशेषता उनका राजनीतिक आत्मविश्वास है। वे अपने निर्णयों और राजनीतिक दृष्टिकोण को सार्वजनिक रूप से रखने में संकोच नहीं करते। कई बार उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखा, जिन्हें लेकर मतभेद की संभावना पहले से स्पष्ट थी। राजनीति में यह गुण दोधारी तलवार की तरह होता है। आत्मविश्वास नेतृत्व को दृढ़ता देता है, लेकिन वही दृढ़ता यदि अत्यधिक दिखाई दे तो आलोचना का कारण भी बन सकती है। उनके समर्थक उन्हें दृढ़ और निर्णायक नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उनकी शैली को टकरावपूर्ण मान सकते हैं। एक संतुलित व्यक्तित्व-चित्र के लिए इन दोनों दृष्टियों को समझना आवश्यक है।



‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ के कुशल चितरे
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश
छत्तीसगढ़ के विकास को स्थानीय दृष्टि
देने का प्रयास
धान खरीदी और किसानों को आर्थिक
राहत देने का महत्वपूर्ण निर्णय
गोधन, गौठान को अर्थव्यवस्था से जोड़े



दुनिया में छा गया था भूपेश के विकास का जादू

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनैतिक व्यक्तित्व विशाल एवं अपने आप में संघर्ष की दास्तान है। एक ओर जहाँ उनका व्यक्तित्व सरल एवं मिलनसार है वहीं उनकी कार्यशैली को देखें तो वह अदम्य जिजीविषा से भरी हुई दिखाई देती है। “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” और “छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी.. नरवा, गरवा, घुरुवा, बारी..येला बचाना हे संगवारी” जैसे नारे केवल एक राजनीतिक नारे नहीं थे, बल्कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विकास-यात्रा को एक स्थानीय दृष्टि देने का प्रयास भी था।

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, ग्रामीण जीवन, संस्कृति और प्रशासन को लेकर कई ऐसे निर्णय लिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति और सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित किया। उनके कार्यकाल का मूल्यांकन आज भी राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग-अलग ढंग से किया जाता है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उनकी सरकार

ने विकास के एजेंडे में किसान, गांव, स्थानीय अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ी अस्मिता को प्रमुख स्थान दिया। भूपेश बघेल के कृतित्व को समझने के लिए उनकी सरकार की नीतियों को केवल योजनाओं की सूची के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। उनके शासन की मूल प्रवृत्ति इस बात में दिखाई देती है कि उन्होंने राज्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में देखने की कोशिश की। इसी कारण उनके कार्यकाल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले सबसे अधिक चर्चा में रहे।

कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार बनाने की कोशिश



छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका को देखते हुए भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा. धान खरीदी और किसानों को आर्थिक राहत देने के निर्णय उनकी सरकार की प्रमुख पहचान बने. राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को इनपुट सहायता देने का प्रयास किया गया. इसका उद्देश्य किसानों की आय को सहारा देना और कृषि को अधिक टिकाऊ बनाना था. धान खरीदी के मामले में भी उनकी सरकार ने राज्य की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया. किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की कोशिश ने ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की स्वीकार्यता बढ़ाने में भूमिका निभाई. हालांकि इन योजनाओं की वित्तीय स्थिरता, केंद्र-राज्य संबंधों और दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर राजनीतिक बहस भी हुई, लेकिन किसान-केंद्रित नीति को छत्तीसगढ़ के शासन मॉडल का प्रमुख विषय बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को दिया जा सकता है.

गोधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया प्रयोग

भूपेश सरकार की सबसे चर्चित प्रयासों में गोधन न्याय योजना रही. गोबर की खरीद और उससे जुड़े आर्थिक मॉडल की कल्पना पारंपरिक ग्रामीण संसाधन को आय के साधन में बदलने की कोशिश थी. इसके पीछे विचार था कि पशुपालन, जैविक खाद, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण रोजगार को एक-दूसरे से जोड़ा जाए. इस योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया. इसकी वास्तविक आर्थिक उपयोगिता और व्यापक प्रभाव पर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन नीति की दृष्टि से यह प्रयोग महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें ग्रामीण जीवन की एक सामान्य वस्तु को आर्थिक गतिविधि से जोड़ने की कोशिश की गई. इसी सोच से जुड़ी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रीपा) जैसी पहल का उद्देश्य गांवों में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करना था. इससे यह संकेत मिला कि ग्रामीण विकास को केवल कृषि तक सीमित रखने के बजाय गैर-कृषि गतिविधियों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है. किसान आज भी चाहते हैं कि इन योजनाओं का लाभ लेने उन्हें एक बार और मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए.



लघु वनोपज और आदिवासी अर्थव्यवस्था पर जोर



छत्तीसगढ़ के आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों के संदर्भ में लघु वनोपज का विशेष महत्व है. भूपेश सरकार ने तेंदूपत्ता सहित विभिन्न लघु वनोपजों के संग्रहण, मूल्य संवर्धन और विपणन को लेकर नीतिगत प्रयास किए. उद्देश्य यह था कि जंगल से मिलने वाले संसाधनों का वास्तविक लाभ उन समुदायों तक पहुंचे, जिनकी आजीविका उनसे जुड़ी है. लघु वनोपज की खरीद और स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की कोशिश ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया. इससे आदिवासी समाज की पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों को सरकारी नीति के केंद्र में लाने का प्रयास दिखाई देता है.

महिला समूहों और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा

उनके शासनकाल में महिला स्व-सहायता समूहों को भी कई योजनाओं से जोड़ा गया. ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया गया. इसके पीछे मूल विचार था कि ग्रामीण विकास में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़े और परिवार की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित हों. यह दृष्टिकोण उनके शासन मॉडल के उस हिस्से को दर्शाता है जिसमें सरकार की भूमिका केवल सहायता देने वाली संस्था की न होकर स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली संस्थाओं में उनकी सीधी भागीदारी हो.



छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विकास के विमर्श से जोड़ना

उनके कृतित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक क्षेत्र में दिखाई देता है। उनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी भाषा, लोककला, लोकपर्व और पारंपरिक जीवनशैली को सार्वजनिक जीवन में अधिक प्रमुखता मिली। हरेली, तीजा, पोला जैसे स्थानीय पर्वों को सरकारी स्तर पर व्यापक पहचान देने की कोशिश की गई। यह पहल केवल सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे छत्तीसगढ़ की अपनी सांस्कृतिक पहचान को राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में स्थापित करने की सोच दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ी अस्मिता को विकास की अवधारणा के साथ जोड़ना उनके शासन की विशिष्ट विशेषता रही।



राम वन गमन पर्यटन परिपथ और धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत

छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए राम वन गमन पर्यटन परिपथ की अवधारणा को आगे बढ़ाया गया। राज्य की उन जगहों को विकसित करने का प्रयास किया गया, जिन्हें रामायण परंपरा से जोड़ा जाता है। इस पहल में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को जोड़ने का प्रयास दिखाई देता है। यदि ऐसे स्थलों पर पर्यटन का स्थायी विकास हो, तो इससे स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प, परिवहन और छोटे व्यवसायों को लाभ मिल सकता है।



स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास

उनकी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कई योजनाएं और संस्थागत पहलें कीं। हाट बाजार क्लीनिक योजना जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना था। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के उन्नयन और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना पर जोर दिया गया। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूलों की अवधारणा को आगे बढ़ाया। इन विद्यालयों को लेकर अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। हालांकि किसी भी शिक्षा सुधार का वास्तविक मूल्यांकन उसके दीर्घकालीन शैक्षणिक परिणामों से ही किया जा सकता है, फिर भी सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जाती है।

प्रशासन में स्थानीय प्राथमिकताओं की छाप

उनके सरकार की एक बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने प्रशासनिक निर्णयों को स्थानीय राजनीतिक-सामाजिक प्राथमिकताओं से जोड़ने की कोशिश की। उनके कार्यकाल में यह संदेश बार-बार सामने आया कि छत्तीसगढ़ का विकास केवल बड़े उद्योगों और शहरी अधोसंरचना से नहीं, बल्कि गांव, किसान, आदिवासी, महिला और छोटे उद्यमी को मजबूत करने से भी होगा। यही दृष्टिकोण उनके कृतित्व को एक अलग पहचान देता है। उनके शासन मॉडल में बड़े विकास कार्यों के साथ-साथ छोटे और स्थानीय आर्थिक चक्रों को महत्व दिया गया।



उपलब्धियों के साथ चुनौतियों का भी मूल्यांकन

किसी भी सरकार के कृतित्व का मूल्यांकन केवल उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं किया जा सकता। उनकी सरकार को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नीतियों के वित्तीय भार, प्रशासनिक क्रियान्वयन, रोजगार, कानून-व्यवस्था और विभिन्न राजनीतिक विवादों को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए। इसलिए उनके कार्यकाल का संतुलित मूल्यांकन करते समय उपलब्धियों के साथ इन आलोचनाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। फिर भी उनके पांच वर्ष के कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास की चर्चा में स्थानीयता को केंद्रीय स्थान देने की कोशिश की। उन्होंने किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, गोधन, लघु वनोपज, महिला समूह, स्थानीय संस्कृति और सरकारी शिक्षा जैसे विषयों को राजनीतिक प्राथमिकता बनाया।

एक अलग विकास-दृष्टि की विरासत

उनके कृतित्व का मूल्यांकन समय के साथ और व्यापक होगा। उनकी योजनाओं की वास्तविक सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उन्होंने किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर कितना स्थायी प्रभाव डाला। लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि उनके कार्यकाल ने छत्तीसगढ़ में विकास के एक ऐसे मॉडल पर बहस को आगे बढ़ाया, जिसमें स्थानीय संसाधन, स्थानीय संस्कृति और स्थानीय समुदाय विकास के केंद्र में रहे। उनकी सरकार का सबसे उल्लेखनीय योगदान शायद यही था कि उसने छत्तीसगढ़ को केवल एक प्रशासनिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले प्रदेश के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी योजनाओं की सफलता-असफलता पर मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक निष्कर्ष अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल ने प्रदेश की राजनीति में किसान, गांव और छत्तीसगढ़िया अस्मिता को जिस प्रमुखता से स्थापित किया, वह आने वाले वर्षों के राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती रहेगी। किसी भी मुख्यमंत्री की वास्तविक विरासत केवल उसके कार्यकाल की योजनाओं में नहीं, बल्कि उस सोच में होती है जिसे वह शासन के माध्यम से समाज में स्थापित करता है। भूपेश बघेल की विरासत को इसी कसौटी पर देखा जाए तो उनका कृतित्व छत्तीसगढ़ के स्थानीय जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास के रूप में सामने आता है।

कौन बनेगा करोड़पति में भी छाए 'कका'

कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी-18) में छत्तीसगढ़ से आए युवा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का उल्लेख किया। आईआईटी मुंबई के टॉपर रहे इस छात्र ने बताया कि यहां प्रवेश के लिए आ रही परेशानियों के संबंध में श्री बघेल को जानकारी होने पर उन्होंने तत्काल उसकी मदद की। तभी वह आज इस संस्थान में अध्ययन कर पा रहा है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम टेहका निवासी 23 वर्षीय योगेश साहू ने शानदार प्रदर्शन कर हुए 50 लाख रुपये जीते। योगेश ने यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। KBC के मंच पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ के युवा योगेश ने अपनी मेधा और ज्ञान का लोहा मनवाया है। इस शानदार सफलता के बाद प्रदेश भर में खुशी का माहौल है और लोग युवा की इस उपलब्धि पर गर्व जता रहे हैं। युवक की इस ऐतिहासिक सफलता पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने युवक के कठिन दौर और उसके संघर्ष के दिनों को याद करते हुए साझा किया कि किस तरह जब वह समस्याओं से जूझ रहा था, तब उसकी शिक्षा और अन्य जरूरतों को कांग्रेस सरकार के समय शासन-प्रशासन द्वारा मदद की गई।



अब मैं मन का गुलाम नहीं

शाहजहाँपुर जेल (उ.प्र.) से ब्रह्माकुमार जोगेन्द्र की स्वीकारोक्ति

मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ। मैं बचपन से ही बहुत क्रोधी था। बड़े होने पर भी क्रोध कम नहीं हुआ। माता-पिता ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद युगल ने भी समझाया, साधू-संन्यासियों ने भी समझाया पर मैंने किसी की नहीं मानी और मदिरा पीना शुरू कर दिया। कहावत है, 'भूत के हाथ में भाला' मेरा भी वही हाल हुआ। गलत संगत में पड़कर झगड़ा कर लिया। मेरे साथी ने गोली मार दी और 307 का मुकदमा मेरे पर दर्ज हो गया। जब मैं जेल में आया तब मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे शान्ति की इच्छा हुई तो रामायण पाठ करना शुरू किया, फिर भी क्रोध शान्त नहीं होता था। एक भाई ने मुझे ब्रह्माकुमारीज की साप्ताहिक ज्ञान की पुस्तक दी, मैंने उसे पढ़ा, पढ़ते ही महसूस हुआ कि कोई काँटों से फूलों की तरफ मुझे खींच रहा है। जेल में ही ब्रह्माकुमारीज की क्लास लगती थी, वहाँ पर मुझे प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया गया। मैं रोज़ ईश्वरीय ज्ञान सुनने लगा। इसके बाद मुझे लगा कि खोया हुआ सच्चा पिता मुझे प्राप्त हो गया है। ईश्वरीय ज्ञान में चलने से सब नशे जेल में ही छूट गये। क्रोध शान्त हो गया और मुझे शान्ति मिलने लगी। 'आत्मा परमात्मा की पहचान' और 'दिव्य गुणों का गुलदस्ता' पुस्तकें पढ़ने से बहुत ज्ञान मिला। फिर मैं शाम और सुबह योग लगाने लगा।

अब मैं शान्ति-प्रेमपूर्वक और नम्रता से चल रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि बाबा मेरे साथ, हाथ में हाथ लिए चल रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और लोग मुझसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और कहते हैं कि इस को तो जाने क्या मिल गया है जो खोया हुआ रहता है। मेरा यही अनुभव है कि जब तक दवा ठीक तरह से नहीं होती है तब तक रोग नष्ट नहीं होता है। बाबा अब मेरा वैद्य हो गया, उन्होंने मेरे रोग की सही दवा दे दी जिससे रोग जड़ से गायब हो गया है और जिन्दगी शान्ति से जीने लगा हूँ। अब यदि मुझे कोई अपशब्द या कटु वचन बोलता है तो मैं बाबा को ढाल बना लेता हूँ। जैसे सीता एक तिनके की ओट से रावण से बात कर लेती थी ऐसे ही मैं आत्मा रूपी सीता, मायावी विचारों को बाबा की ओट से खत्म कर देती हूँ लेकिन पास नहीं आने देती हूँ। वाह रे वाह बाबा, कितना आनन्दित हूँ! अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे खजाने मेरे ही पास हैं। अब मैं मन का गुलाम नहीं हूँ। अब जान गया हूँ कि मैं आत्मा राजा, मन मंत्री और कर्मन्द्रियाँ मेरी नौकर-चाकर हैं।



23

August

Birthday



कका को जन्मदिन की हार्दिक बधाई

आपके विचार और जनता के प्रति
आपका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता है...

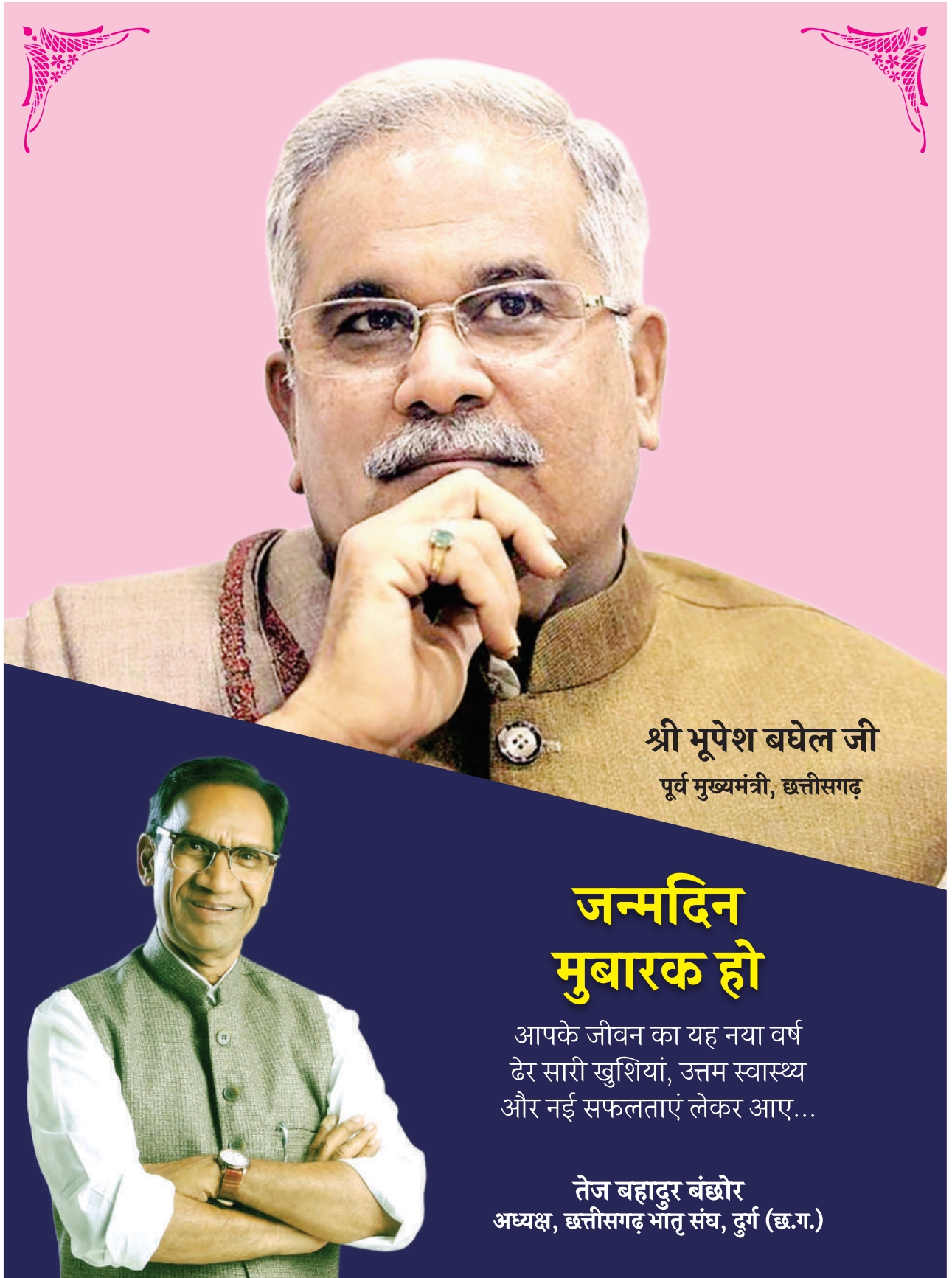


पूर्णचन्द्र 'कोको' पाढ़ी

पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं
पूर्व प्रदेशाध्यक्ष युवक कांग्रेस

अनूप वर्मा

प्रदेश महासचिव, युवक कांग्रेस
पूर्व चेयरमैन, आई.टी. सेल



श्री भूपेश बघेल जी
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

जन्मदिन मुबारक हो

आपके जीवन का यह नया वर्ष
ढेर सारी खुशियां, उत्तम स्वास्थ्य
और नई सफलताएं लेकर आए...

तेज बहादुर बंछोर
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भातृ संघ, दुर्ग (छ.ग.)



श्री भूपेश बघेल जी

पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



**आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि
आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रदेश की जनता की
सेवा इसी तत्परता से करते रहें...**

**प्रो.
जय चण्डी
मिनरल्स**



कौशल वर्मा
इंजीनियर



प्रिस वर्मा



जानकी वर्मा

**वर्मा
कंस्ट्रक्शन**





जिसके लिए उजड़े 40 से अधिक गांव, क्या उसके विकास में किसान और मजदूर भी हिस्सेदार बनें?

देश की औद्योगिक रीढ़ और 'मिनी इंडिया' के रूप में पहचाने जाने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के 47 हजार करोड़ रुपये के नए विस्तारीकरण योजना ने विकास के साथ-साथ कई अनसुलझे सवाल खड़े कर दिए हैं. 40 से अधिक गांवों को उजाड़कर बसाए गए इस ऐतिहासिक औद्योगिक नगरी का मूल ढांचा आज प्रशासनिक उपेक्षा, घटते नियमित रोजगार और जर्जर टाउनशिप जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) की औद्योगिक ईकाई भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में जहां एक ओर क्षमता विस्तार की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय किसान, मजदूर, ठेका श्रमिक और एमएसएमई उद्योग इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि अरबों रुपये के इस निवेश में शहर की वास्तविक हिस्सेदारी और नागरिक भविष्य का स्थान कहां है?

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भिलाई केवल एक इस्पात संयंत्र का नाम नहीं है. यह स्वतंत्र भारत के औद्योगिक निर्माण की उस कहानी का हिस्सा है, जिसमें बड़े उद्योगों के साथ एक पूरा शहर बसाया गया. पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के प्रयासों से भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई. इसके लिए 40 से अधिक गांवों की जमीन लेकर एक आधुनिक औद्योगिक शहर और टाउनशिप विकसित की गई. यही भिलाई आगे

विस्तारीकरण योजना का किसे मिला लाभ ?

टाउनशिप, श्रमिकों और स्थानीय उद्योगों के भविष्य पर सवाल

भिलाई का अगला सवाल उत्पादन नहीं, भागीदारी है

47 हजार करोड़ का विस्तार, लेकिन भिलाई के हिस्से में क्या?

चलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित इस्पात केंद्रों में शामिल हुआ और कई बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी हासिल कर अपनी उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का लोहा मनवाता रहा. लेकिन आज उसी भिलाई के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या जिस शहर ने देश के औद्योगिक विकास में इतना बड़ा योगदान दिया, उसके अपने भविष्य, स्थानीय रोजगार, किसानों, श्रमिकों और नागरिक सुविधाओं की चिंता विकास की प्राथमिकताओं में शामिल है?

एक तरफ सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण पर करीब 47 हजार करोड़ रुपये

स्कूल और अस्पतालों का भविष्य क्या?

भिलाई का सबसे मजबूत सामाजिक मॉडल उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था रही है। बीएसपी के स्कूलों ने हजारों बच्चों को शिक्षा दी और जेएलएन अस्पताल सहित स्वास्थ्य संस्थानों ने शहर के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं। लेकिन स्थानीय संगठनों का आरोप है कि टाउनशिप के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं। इसी तरह कैंप, खुर्सीपार और सेक्टर क्षेत्रों के कई विद्यालयों के बंद होने की बात कही जा रही है। यह सिर्फ भवनों के बंद होने का मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि क्या औद्योगिक शहर की अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को भी विस्तारीकरण का हिस्सा बनाया जा रहा है?

के निवेश की चर्चा है, दूसरी ओर टाउनशिप के बुनियादी ढांचे, स्कूल, अस्पताल, खेल सुविधाओं, ठेका श्रमिकों और स्थानीय उद्योगों की स्थिति को लेकर नागरिकों एवं श्रमिक संगठनों में असंतोष बढ़ रहा है।

भिलाई क्यों बना था देश का औद्योगिक गौरव?

भिलाई की स्थापना के पीछे केवल एक कारखाना लगाने का उद्देश्य नहीं था। यह एक ऐसा औद्योगिक मॉडल था, जिसमें उत्पादन के साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पेयजल और सामाजिक सुविधाओं को भी जोड़ा गया था। भिलाई की भौगोलिक स्थिति भी इसकी बड़ी ताकत रही। लौह अयस्क में उच्च लौह मात्रा, आसपास चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा रेल नेटवर्क से जुड़ाव ने इसे इस्पात उद्योग के लिए अनुकूल बनाया। मुंबई-हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण भिलाई को देश के विभिन्न हिस्सों तक कच्चा माल पहुंचाने और तैयार इस्पात उत्पादों को बाजार एवं बंदरगाहों तक भेजने में भी सुविधा मिली। विशाखापत्तनम, कोलकाता और पारादीप जैसे प्रमुख बंदरगाहों तक रेल कनेक्टिविटी ने भिलाई की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत किया। बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे अन्य प्रमुख इस्पात संयंत्रों की तुलना में भिलाई को अपेक्षाकृत शांत और व्यवस्थित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया गया। यही कारण रहा कि भिलाई की पहचान केवल उत्पादन केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित औद्योगिक नगरी के रूप में बनी।

70 हजार कर्मचारियों से घटकर मात्र 12 हजार ही कार्यरत

भिलाई इस्पात संयंत्र में कभी करीब 70 हजार कर्मचारी काम करते थे। हजारों परिवारों की रोजी-रोटी सीधे संयंत्र से जुड़ी थी और इसके साथ हजारों छोटे-बड़े व्यवसाय एवं उद्योग भी फलते-फूलते थे। आज नियमित कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आई है। श्रमिक संगठनों का दावा है कि यह संख्या अब करीब 12 से 15 हजार के आसपास रह गई है। कर्मचारियों की संख्या घटने के साथ ठेका व्यवस्था बढ़ी है। यहीं से दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या स्थायी रोजगार के स्थान पर बढ़ती ठेका व्यवस्था ने श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को कमजोर किया है? श्रमिक संगठनों का आरोप है कि ठेका श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, भत्ते और अन्य वैधानिक सुविधाओं का

पूरा लाभ नहीं मिल रहा। कम मैनपावर में बढ़ते वर्कलोड को लेकर भी कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ स्थानीय संगठनों का यह भी आरोप है कि संयंत्र के शीर्ष प्रबंधन में बढ़ी संख्या में ऐसे अधिकारी रहे हैं जिनका भिलाई से दीर्घकालिक सामाजिक और स्थानीय जुड़ाव नहीं रहा। उनके अनुसार इसका असर स्थानीय परिस्थितियों और श्रमिकों की समस्याओं की समझ पर भी पड़ा है। हालांकि, इस दावे पर प्रबंधन का पक्ष भी सामने आना जरूरी है।

विस्तारीकरण 47 हजार करोड़ का, टाउनशिप की हालत पर सवाल

भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तारीकरण को लेकर निवेश लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है। स्थानीय संगठनों का कहना है कि करीब एक दशक पहले जिस विस्तार योजना की लागत लगभग 25 हजार करोड़ रुपये बताई जाती थी, वह अब बढ़कर करीब 47 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इतने बड़े निवेश के बीच टाउनशिप की स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। कभी बीएसपी के पास कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लगभग 36 हजार आवास होने की बात कही जाती थी। दस से अधिक सेक्टरों में फैली टाउनशिप तथा खुर्सीपार के जोन-1, 2 और 3 जैसे क्षेत्रों ने भिलाई की विशिष्ट

‘मिनी इंडिया’ की पहचान बचाने की चुनौती

भिलाई को ‘मिनी इंडिया’ इसलिए कहा गया क्योंकि देश के लगभग हर हिस्से से लोग यहां आए और मिलकर एक औद्योगिक समाज बनाया। अलग-अलग भाषा, संस्कृति, धर्म और क्षेत्र के लोगों ने मिलकर भिलाई को आकार दिया। लेकिन शहर की औद्योगिक रीढ़ कमजोर पड़ती है, स्थानीय रोजगार घटता है, छोटे उद्योग बंद होते हैं और सामाजिक सुविधाएं सीमित होती हैं तो इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं, शहर की सामाजिक पहचान पर भी पड़ता है। आज जरूरत इस बात की है कि भिलाई के विकास को केवल स्टील उत्पादन के आंकड़ों से नहीं मापा जाए। विकास का पैमाना यह भी हो कि, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला? कितने स्थानीय उद्योग बढ़े? कितने ठेका श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन मिला? कितने स्कूल और अस्पताल मजबूत हुए? टाउनशिप की नागरिक सुविधाएं कितनी बेहतर हुईं?

पहचान बनाई. स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी संख्या में आवास आज भी उपलब्ध हैं, लेकिन कई जगहों पर रखरखाव और नागरिक सुविधाओं की स्थिति अपेक्षित स्तर की नहीं है. वर्ष 2001 से 2003 के बीच आई लीज स्कीम के बाद आवास व्यवस्था में भी बदलाव आया. सवाल यह है कि जब एक ओर नए औद्योगिक निवेश पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो पुराने सामाजिक एवं नागरिक ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है?

नगर निगम के पैसे से टाउनशिप क्यों?

भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में से करीब 35 वार्ड टाउनशिप क्षेत्र से जुड़े हैं. स्थानीय नागरिक एवं श्रमिक संगठनों का दावा है कि नगर निगम हर वर्ष टाउनशिप के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पेवर ब्लॉक, सौंदर्यीकरण, डोम शेड और खेल मैदान जैसे कार्यों पर बड़ी राशि खर्च करता है. यहीं से करदाताओं का सवाल सामने आता है क्या आम जनता से मिलने वाला नगर निगम का पैसा उस क्षेत्र के विकास पर खर्च होना चाहिए, जिसके पास स्वयं एक विशाल औद्योगिक संस्थान और संसाधन हैं? यदि टाउनशिप के रखरखाव की जिम्मेदारी का स्वरूप बदल चुका है, तो राज्य शासन, नगर निगम और बीएसपी के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना जरूरी है.

खेलों की धरती पर सन्नाटा

भिलाई ने देश को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं. बीएसपी की खेल संस्कृति कभी देश के अन्य औद्योगिक संस्थानों के लिए उदाहरण मानी जाती थी. स्थानीय लोगों का कहना है कि खेल सुविधाओं और संस्थागत समर्थन में कमी आने से यह गौरवशाली परंपरा कमजोर हो रही है. यदि खेल विभाग और खेल अधोसंरचना कमजोर होती है, तो इसका नुकसान केवल वर्तमान खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी होगा.

पानी भी उसी भिलाई का, सवाल भी उसी का

भिलाई की टाउनशिप को तांदुला, खरखरा और गंगरेल जल स्रोतों से पानी मिलता रहा है. जिस शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया, वहां आज पेयजल की गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट, सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आना व्यवस्था की समीक्षा की मांग करता है. भिलाई के विकास का मूल मॉडल ही यह था कि औद्योगिक उत्पादन के साथ नागरिक जीवन की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए. इसलिए अब इस मॉडल की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन जरूरी है.

सीएसआर पर भी उठ रहे सवाल

स्थानीय संगठनों द्वारा बीएसपी के सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. उनका दावा है कि लाभ का एक निर्धारित हिस्सा सामाजिक दायित्वों पर खर्च किया जाना

चाहिए, लेकिन स्थानीय क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा. यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सीएसआर व्यय की कानूनी व्यवस्था कंपनियों की पात्रता और लागू प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है. इसलिए वास्तविक स्थिति जानने के लिए बीएसपी के आधिकारिक सीएसआर व्यय, परियोजनाओं और उनके लाभार्थियों के आंकड़ों की सार्वजनिक समीक्षा जरूरी है.

बीएसपी से निकली आर्थिक धारा अब क्यों कमजोर?

भिलाई इस्पात संयंत्र के कारण दुर्गा-भिलाई क्षेत्र में इंजीनियरिंग, परिवहन, स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग, फेब्रिकेशन और अन्य छोटे-मझोले उद्योगों का बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ. लेकिन स्थानीय उद्योग जगत का दावा है कि बीएसपी पर निर्भर बड़ी संख्या में छोटे एवं मध्यम उद्योग या तो बंद हो चुके हैं या भारी बैंक ऋण के दबाव में हैं. यदि यह स्थिति सही है, तो 47 हजार करोड़ रुपये के विस्तार में स्थानीय एमएसएमई को कितना अवसर मिलेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होना चाहिए. बड़ा निवेश तभी बड़ा विकास कहलाएगा, जब उसकी आर्थिक धारा आसपास के छोटे उद्योगों, स्थानीय युवाओं और श्रमिकों तक भी पहुंचे.

किसानों का सवाल भी अनदेखा न हो

भिलाई की स्थापना के समय उद्योग के लिए जिन गांवों की जमीन ली गई, उनके किसानों और विस्थापित परिवारों ने औद्योगिक विकास के लिए अपना योगदान दिया. आज स्थानीय संगठनों का सवाल है कि दशकों बाद उन परिवारों और किसानों की अगली पीढ़ी के लिए विकास का लाभ क्या है? स्थानीय हितों में रोजगार, कौशल विकास, व्यापारिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास से जुड़े मुद्दे शामिल हैं. इसलिए नए विस्तारीकरण के साथ स्थानीय युवाओं, किसानों और प्रभावित परिवारों के लिए स्पष्ट सामाजिक-आर्थिक रोडमैप भी होना चाहिए.

अब सिर्फ विस्तार नहीं, समग्र विकास चाहिए

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तारीकरण छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा अवसर है. लेकिन इस अवसर को केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित करना शहर के साथ न्याय नहीं होगा. स्थानीय नागरिकों और मजदूर संगठनों की मांग है कि केंद्रीय श्रम आयुक्त भिलाई का दौरा कर ठेका श्रमिकों की स्थिति की निष्पक्ष जांच करें. साथ ही बीएसपी प्रबंधन, सेल, केंद्र सरकार, राज्य शासन और नगर निगम मिलकर टाउनशिप, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और स्थानीय उद्योगों की स्थिति की समीक्षा करें. भिलाई ने देश के लिए इस्पात बनाया है. अब वक्त है कि विकास की इस भट्टी से भिलाई के लोगों के लिए भी रोजगार, सम्मान, बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित भविष्य निकले. क्योंकि सवाल केवल 47 हजार करोड़ के निवेश का नहीं है. सवाल यह है कि इस निवेश से भिलाई कितना बदलेगा और उस बदलाव में भिलाई के आम नागरिक की हिस्सेदारी कितनी होगी?

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस

की प्रदेशवासियों को

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं



■ सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी

■ सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक खाद का वितरण

■ समर्थन मूल्य का उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराकर पीडीएस के लिए नान और एफसीआई को सौपना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला- बिलासपुर (छ.ग.)



नगरीय निकाय चुनाव

प्रदेश में जल्द बजेगा नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल

दिसंबर महीने में खत्म हो रहा है 15 नगरीय निकायों का कार्यकाल, चुनावी तैयारी शुरू

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

छत्तीसगढ़ में दो साल बाद फिर से एक बार चुनावी माहौल गरमाएगा. विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय निकायों के चुनाव के लिए सियासी कवायद शुरू हो गई है. दिसंबर महीने में जिन नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके चुनाव के लिए दो तरफा तैयारी शुरू हो गई है. चुनाव के लिए एक ओर जहां जहां शासन, राज्य निर्वाचन आयोग और निकाय प्रशासन द्वारा प्री इलेक्शन की प्रक्रिया जारी है. वहीं कांग्रेस और भाजपा सहित चुनाव मैदान में बतौर निर्दलीय भाग्य आजमाने वाले दावेदारों ने भी कमर कस ली है. प्रदेश में दो नई नगर पंचायत को मिलाकर कुल 194 में नगरीय निकाय हैं. इनमें से 3 माह बाद 4 नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इन सभी निकायों में दिसंबर महीने में चुनाव होना है. इसके साथ ही 2 नई नगर पंचायतों के भी चुनाव प्रस्तावित हैं. यानी कुल 17 नगरीय निकायों के चुनाव सम्पन्न कराने की तैयारी चल रही है.

प्रदेश के 17 नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रारंभिक तैयारी चल रही है. जिन 17 नगरीय निकायों में दिसंबर महीने में चुनाव होना है. उसके लिए कवायद शुरू हो गई है. दिसंबर में होने वाले 17 नगरीय निकायों के तहत 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका, 6 नगर पंचायत और 2 नई नगर पंचायत शामिल हैं.

दिसंबर 2026 में चुनाव वाले निकाय

श्रेणी	संख्या	निकाय
नगर निगम	4	बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली
नगर पालिका	5	जामुल, सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर-चरचा, खैरागढ़
नगर पंचायत	6	प्रेमनगर, मारो, कोंटा, नरहरपुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम
नई नगर पंचायत	2	तमनार, बड़ी करेली

विभागीय सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा परिसीमन और आरक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। 15 निकायों और 2 नवगठित निकायों में परिसीमन और आरक्षण की स्थिति साफ

दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के दौरान होने वाले आम निर्वाचन के सिलसिले में राज्य के 15 नगरीय निकायों तथा 2 नए निकायों की स्थिति साफ हो गई है। 2024 में संपन्न परिसीमन के आधार पर इन निकायों में चुनाव की तैयारी है। जिन नगरीय निगम में दिसंबर महीने में चुनाव प्रस्तावित हैं इनमें शामिल हैं-

नगर निगम

1. न.नि. बीरगांव (रायपुर): 40 सीटें, महापौर/अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला) के लिए आरक्षित.
2. न.नि. भिलाई (दुर्ग): 70 सीटें (2020 परिसीमन), अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त).
3. न.नि. रिसाली (दुर्ग): 40 सीटें (2020 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (महिला).
4. न.नि. भिलाई-चरौदा (दुर्ग): 40 सीटें (2020 परिसीमन), अध्यक्ष पद अन्य पिछड़ा वर्ग (मुक्त).

नगर पालिका

1. न.पा. जामुल (दुर्ग): 20 सीटें, अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला).
2. न.पा. सारंगढ़ (सारंगढ़-बिलाईगढ़): 15 सीटें (2016 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (मुक्त).
3. न.पा. बैकुंठपुर (कोरिया): 20 सीटें, अध्यक्ष पद अनारक्षित

(मुक्त).

4. न.पा. शिवपुरचरचा (कोरिया): 15 सीटें (2020 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला).
5. न.पा. खैरागढ़ (खैरागढ़-छुईखदान-गंडई): 20 सीटें, अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला).

नगर पंचायत

1. न.पं. प्रेमनगर (सूरजपुर): 15 सीटें (2015 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (महिला).
 2. न.पं. नरहरपुर (कांकेर): 15 सीटें (2014 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (मुक्त).
 3. न.पं. कोण्टा (सुकमा): 15 सीटें (2010 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (महिला).
 4. न.पं. भैरमगढ़ (बीजापुर): 15 सीटें (2014 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (मुक्त).
 5. न.पं. भोपालपटनम (बीजापुर): 15 सीटें (2014 परिसीमन), अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (मुक्त).
 6. न.पं. मारो (बेमेतरा): 15 सीटें, अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (मुक्त).
 7. न.पं. तमनार (रायगढ़): 15 सीटें (2026 परिसीमन), इसका वार्ड परिसीमन राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, लेकिन अध्यक्ष व वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शेष है.
 8. न.पं. बड़ी करेली (धमतरी): 15 सीटें, इसमें अध्यक्ष पद, वार्ड परिसीमन एवं वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया अभी शेष है.
- विभाग के निर्देशों के अनुसार, सभी 15 शेष निकायों में महापौर/अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की जाएगी, वहीं नवगठित निकायों में आरक्षण एवं परिसीमन की कार्रवाई जारी है.

आत्मनिर्भर नारी, समृद्ध छत्तीसगढ़ महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय



किसी भी राज्य के विकास की वास्तविक पहचान वहां की महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता से होती है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो परिवार सशक्त होता है, समाज प्रगतिशील बनता है और विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को सुशासन का प्रमुख आधार बनाया है। वर्ष 2026 को “महतारी गौरव वर्ष” के रूप में मनाते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

» डॉ. दानेश्वरी संभाकर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित योजनाएं आज लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल महतारी वंदन योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का सशक्त माध्यम बन चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 66 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही

है। अब तक 29 किस्तों के माध्यम से 18 हजार 805 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ कर रही है। इस योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में आंगनबाड़ी संचालन हेतु 800 करोड़ रुपये, पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये तथा कुपोषण मुक्ति एवं पोषण योजनाओं के लिए 235 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 250 और ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी सदन स्थापित किए जा रहे हैं। अब तक 368 महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें 137 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2026-27 में 250 नए महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में 34 सखी वन-स्टॉप सेंटर संचालित किए हैं। यहां घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और संकटग्रस्त महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 के समन्वय से त्वरित सहायता व्यवस्था भी प्रभावी रूप से संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने सखी वन-स्टॉप सेंटरों के संचालन के लिए डिजिटल एसओपी लागू की है।

महिलाओं की आर्थिक प्रगति को नई गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन और विपणन से जोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार 200 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण कर रही है, जहां महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध होगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतिवर्ष युवा रत्न सम्मान प्रदान किया जाएगा तथा लखपति दीदी भ्रमण योजना के माध्यम से सफल उद्यमियों को देश-विदेश के अध्ययन भ्रमण का अवसर मिलेगा।

बिहान मिशन के अंतर्गत प्रदेश में 2.92 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनसे 31.65 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री के तीन करोड़ लखपति दीदी लक्ष्य में छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 10 लाख 43 हजार से अधिक लखपति दीदी तैयार की हैं। रेडी-टू-ईट निर्माण, कृषि आधारित उद्यम, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा हस्तशिल्प जैसी गतिविधियों ने ग्रामीण महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

महिला निर्माण श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण

सहायता योजना के तहत पात्र बेटियों को 20 हजार रुपये, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत 7,900 रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत अनुदान तथा मिनीमाता महतारी जतन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला श्रमिकों को 20 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 24 हजार से अधिक बालिकाओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है। प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए राज्य सरकार 50 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा रही है। वहीं महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत 42,878 महिला समूहों को 129.46 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया गया है। महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना जमानत 25 हजार रुपये तक का ऋण स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 38 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सुशिक्षा योजना के तहत 2 लाख 18 हजार 139 छात्राओं को प्रतिमाह 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। शुचिता योजना के माध्यम से 2 हजार विद्यालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं तथा लाखों किशोरियों को मासिक स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

महिला समूहों के उत्पाद आज वैश्विक पहचान भी बना रहे हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित जशप्योर ब्रांड “वोकल फॉर लोकल” अभियान का सफल उदाहरण बन चुका है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। वहीं सखी साड़ी-मिलेट कैफे जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।



आज छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का व्यापक अभियान बन चुका है। आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, स्वरोजगार और सम्मानजनक जीवन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयास महिलाओं के जीवन में नए अवसरों के द्वार खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में प्रदेश की महिलाएं आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। यही बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ को “सुशासन से समृद्धि” की ओर निरंतर अग्रसर कर रही है।

लेखक छ.ग. जनसंपर्क विभाग में उपसंचालक के पद पर कार्यरत हैं।

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



श्री राम कुमार टोप्पो

विधायक, सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सीतापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी

मैनपाट, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

मैनपाट, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी

पुलिस थाना उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी

स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी

स्वास्थ्य केन्द्र धौवरपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



वन परिक्षेत्र अधिकारी
लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त अधिकारी व कर्मचारी
तहसील कार्यालय लखनपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी
स्वास्थ्य केन्द्र प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी
तहसील कार्यालय प्रेमनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)

निवेश की नई उड़ान से समृद्धि के पथ पर छत्तीसगढ़

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है परंतु सत्ता पक्ष को जनता की अभिव्यक्ति से अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आता है. लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है. सत्ता पक्ष विपक्ष मुक्त भारत चाहता है फिर भी वे अपने आपको लोकतंत्र का हिमायती बताते हैं. 2014 में देश का विपक्ष इतना कमजोर हो गया था कि उसे विपक्ष की मान्यता भी नहीं मिली थी.



» छ.ग. आजतक ब्यूरो

उद्योग-व्यापार एवं कारोबार को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सकारात्मक माहौल तेजी से तैयार हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों ने निवेशकों के लिए नए अवसरों का वातावरण बनाया है. डबल इंजन सरकार का जोर ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर है, जहां घरेलू और विदेशी निवेशकों को स्पष्ट नीतियां, सुगम प्रक्रियाएं, बेहतर अधोसंरचना और

प्रशासनिक सहयोग मिल सके.

देखा जाये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसी अवधारणा है जिसमें निवेशकों के लिए जटिल शासकीय प्रक्रियाएं आसान बनाई जाती हैं, उद्योग-व्यापार स्थापना की बाधाओं को कम किया जाता है और शासन-प्रशासन को निवेश एवं विकास का सक्रिय सहयोगी बनाकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है. इसके साथ ही राज्य सरकार की अनेक नई पहलें इस बात का संकेत देती हैं कि छत्तीसगढ़ भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए संस्थागत ढांचा भी तैयार कर रहा है.

भरोसे का नया वातावरण, अंजोर विजन-2047

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विभागीय समन्वय बेहतर करने तथा निवेशकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासनिक सुधारों पर जोर है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक से 'अंजोर लाइट - अंजोर लिंकड इम्प्लीमेंटेशन एंड गाइडेंस फॉर होलिस्टिक ट्रेकिंग' तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्णतः अनुदान प्राप्त होगा। यह परियोजना छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्राथमिकता एजेंडा के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहु-क्षेत्रीय तकनीकी सहायता परियोजना का समन्वय आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से होगा। यह पहल संकेत देती है कि छत्तीसगढ़ अब भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ उनके परिणामों की वैज्ञानिक निगरानी की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।



केंद्र और राज्य की नीतियों से मजबूत हुआ औद्योगिक आधार

सरकार की सोच स्पष्ट है कि उद्योगपति और निवेशक को केवल आमंत्रित करना पर्याप्त नहीं है। उसे परियोजना की कल्पना से लेकर उद्योग की स्थापना और संचालन तक सहयोगपूर्ण वातावरण मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया गया है। राज्य नीति आयोग की ओर से सचिव भुवनेश यादव और आईआईएम रायपुर की ओर से निदेशक-प्रभारी प्रो. संजीव पराशर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान, परामर्श, डेटा एनालिटिक्स, शोध और दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। यह समझौता सुशासन, प्रभावी नीति निर्माण और संस्थागत क्षमता विकास के लिए अकादमिक एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता को शासन व्यवस्था से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल है। इससे प्रदेश की विकास योजनाओं में डेटा और शोध आधारित निर्णयों को मजबूती मिलने की संभावना है।

भविष्य की तकनीक से जुड़ता युवा छत्तीसगढ़

उद्योग बदल रहे हैं, तकनीक बदल रही है और रोजगार की प्रकृति भी तेजी से बदल रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने के लिए कौशल प्रशिक्षण में व्यापक बदलाव किए हैं। पारंपरिक ट्रेडों के साथ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंटेनेंस, ड्रोन ऑपरेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और सूर्यमिल जैसे 21वीं सदी के आधुनिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इस वर्ष विशेष रूप से जल वितरण संचालक कोर्स शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 2,770 युवाओं को मल्टी-स्किल प्रशिक्षण देकर सीधे रोजगार से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के 4 लाख 94 हजार 330 युवाओं को विभिन्न रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 2 लाख 74 हजार 934 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। राज्यभर में 375 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं 199 शासकीय एवं 176 अशासकीय के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 9,418 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 7,528 को रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि 6,679 युवा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं तक कौशल विकास पहुंचाने के लिए बस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। बीजापुर में असिस्टेंट मेसन कोर्स शुरू किया गया है। बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर और बीजापुर के पुनर्वास केंद्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने की पहल इस विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश का हिस्सा है।

युवाओं के लिए खुले रोजगार के द्वार

नई औद्योगिक नीति 2024-30 से

युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर

एक हजार रोजगार सृजन पर उद्योगों को मिल रहा विशेष पैकेज

केवल खनिज नहीं, नई अर्थव्यवस्था पर भी नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, आत्मनिर्भरता और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक प्रयास हुए हैं। इसका प्रभाव राज्यों की औद्योगिक नीतियों और निवेश संभावनाओं पर भी दिखाई दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपनी स्थानीय क्षमता और संसाधनों को विकास की नई ताकत में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य की भौगोलिक स्थिति, खनिज संपदा, ऊर्जा क्षमता, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और उभरता बुनियादी ढांचा इसे निवेशकों के लिए विशेष अवसरों वाला प्रदेश बनाता है। निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में भूमि से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व सेवाओं की बड़ी भूमिका होती है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा 'वसुंधरा' वेरिफ़ाई एक्सेसिबल सिस्टम फॉर यूनिफ़ाइड डिजिटल लैंड रिकार्ड्स एंड हिस्टोरिकल आर्चिव्स परियोजना के माध्यम से राजस्व सेवाओं को अधिक सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। परियोजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों के पुराने एवं वर्तमान राजस्व अभिलेखों का संपूर्ण डिजिटलीकरण, संरक्षण और प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए अनावश्यक भागदौड़ से राहत दिलाना है। राजस्व अभिलेखों का डिजिटल ढांचा उद्योग और निवेश की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि से संबंधित स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी किसी भी नई परियोजना की योजना और क्रियान्वयन में सहायक होती है।



काजू-खेती से बाजार तक समृद्धि का नया मॉडल



छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं है। कृषि और बागवानी में नवाचार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिला खेती और बागवानी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। पारंपरिक खेती के साथ किसान अब सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी और काजू जैसी नगदी एवं फल फसलों की ओर भी बढ़ रहे हैं। इनमें जशपुर का काजू किसानों के लिए आय के मजबूत और भरोसेमंद स्रोत के रूप में उभर रहा है। प्रशासन, उद्यान विभाग, रीड्स और नाबार्ड के संयुक्त प्रयासों से जिले में काजू उत्पादन का दायरा बढ़ा है। वर्तमान में लगभग 7,800 किसान करीब 7,800 एकड़ भूमि पर काजू की खेती कर रहे हैं। एक-एक एकड़ भूमि पर काजू की खेती के माध्यम से अनेक किसान बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं। जशपुर में उत्पादित काजू अपनी मिठास, गुणवत्ता और स्वाद के

कारण छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के साथ झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे बाजारों में भी पहचान बना रहा है। यह उदाहरण बताता है कि स्थानीय कृषि उत्पादों को गुणवत्ता, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर ग्रामीण समृद्धि का मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है।

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर : विकास का नया महामार्ग

छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति में मजबूत अधोसंरचना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दूरदर्शी सोच का एक बड़ा उदाहरण रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यह परियोजना केवल दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क नहीं, बल्कि देश के मध्य भाग को पूर्वी समुद्री तट से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण आर्थिक मार्ग है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होने से सड़क परिवहन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। मजबूत सड़कें और आधुनिक लॉजिस्टिक सुविधाएं उद्योगों के लिए लागत कम करने और बाजार तक तेज पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। कॉरिडोर से माल परिवहन अधिक सुगम और प्रभावी हो सकेगा। उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी।

विशाखापट्टनम बंदरगाह तक बेहतर संपर्क छत्तीसगढ़ के उद्योगों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच की नई संभावनाएं खोल सकता है। निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच मजबूत हो सकती है।



औद्योगिक क्लस्टर और रोजगार के नए अवसर

कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, कांकेर और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार की संभावना है। स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, खाद्य प्रसंस्करण और एमएसएमई क्षेत्र को बेहतर परिवहन नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निर्माण के दौरान रोजगार देती हैं, वहीं उनके पूरा होने के बाद परिवहन, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, सेवा क्षेत्र और नई औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। निवेश, उद्योग और कौशल विकास का यह परस्पर संबंध प्रदेश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन सकता है।



बस्तर : सुरक्षा से विकास और विश्वास की ओर

छत्तीसगढ़ की बदलती विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बस्तर में दिखाई देता है। कभी गोलियों की आवाज, विस्फोट और भय के वातावरण के लिए पहचाने जाने वाले अनेक दूरस्थ क्षेत्रों में अब विकास और जनजीवन की नई तस्वीर उभर रही है। जिन गांवों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां अब बच्चों की पढ़ाई और विकास गतिविधियों की आवाज सुनाई दे रही है। जिन रास्तों पर कभी संघर्ष की खबरें प्रमुख थीं, वहां सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की कोशिशें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा और विकास की दोहरी रणनीति के बीच राज्य सरकार का फोकस बस्तर के लोगों का भरोसा जीतने और क्षेत्र को शिक्षा, रोजगार, पर्यटन तथा बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर है। अबूझमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि वर्षों से शिक्षा की प्रतीक्षा कर रहे दूरस्थ क्षेत्र तक अवसर पहुंचाने का प्रयास है। नारायणपुर के दूरस्थ इलाकों में 50 से अधिक स्कूलों को दोबारा शुरू किए जाने से बच्चों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है। इसी प्रकार बस्तर का चर्चित पुर्वती गांव, जिसे कभी नक्सली गतिविधियों का मजबूत केंद्र माना जाता था, अब सड़क और बिजली से जुड़ने के बाद बदलते परिदृश्य का उदाहरण बनकर सामने आया है।

पर्यटन, कृषि और वनोपज के लिए खुलेंगे नए द्वार

बेहतर सड़क और संपर्क सुविधाओं का एक बड़ा लाभ पर्यटन क्षेत्र को भी मिल रहा है। चित्तकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर और बस्तर के सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच से स्थानीय अर्थव्यवस्था में होटल, परिवहन, गाइड और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों के लिए अवसर बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ कृषि और वनोपज की दृष्टि से भी समृद्ध प्रदेश है। बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक व्यवस्था किसानों तथा वनोपज संग्राहकों को बाजार तक पहुंचने में सहायक हो सकती है। परिवहन समय और लागत में कमी का लाभ सीधे उत्पादक की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।



ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग तक

छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को केवल निवेश के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता। इसका व्यापक उद्देश्य नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाना भी है। एक ओर निवेशक के लिए प्रक्रिया आसान हो, दूसरी ओर आम नागरिक को राजस्व दस्तावेज घर बैठे मिलें; युवा आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करें; किसान नई फसलों से बेहतर आय अर्जित करें और दूरस्थ बस्तर तक स्कूल, सड़क तथा बिजली पहुंचे, तभी विकास का वास्तविक अर्थ पूरा होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का विस्तार अब ईज ऑफ लिविंग तक पहुंचा है, आर्थिक विकास सामाजिक समृद्धि में बदलने लगी है। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की नीतियों और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की विकास योजनाओं के बीच बनता समन्वय छत्तीसगढ़ के लिए नए अवसरों का आधार तैयार कर रहा है। आज का छत्तीसगढ़ एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां निवेश के लिए भरोसा, उद्योग के लिए सुविधाएं, युवाओं के लिए कौशल, किसानों के लिए नए बाजार, नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विकास की पहुंच एक साथ प्रदेश की प्रगति को गति दे रही है।

खतरनाक है,

अपराध का राजनीतिकरण



सुप्रीम कोर्ट में पेश एडीआर रिपोर्ट में खुलासा

» अनिल मानिकपुरी

प्रेम, शांति, सद्भाव के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले भारत से सदैव विश्व के लोग यह उम्मीद करते हैं कि सुनहरे अतीत की तरह वर्तमान और भविष्य में भी हमें जीवन मूल्यों का संदेश मिलेगा। हजारों साल से हमारा देश इस मामले में विश्व को रास्ता दिखाते रहा है। यही वजह है कि भारत को विश्वगुरु के गौरवशाली तमगों के रूप में जाना जाते रहा है। कहने को तो आज भी विश्वगुरु से लेकर सुपर पॉवर और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क कहा जा रहा है। लेकिन इस दावे की कसौटी पर हम कितने खरे उतर रहे हैं, इसकी ताजा-तरीन मिसाल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक सनसनीखेज रिपोर्ट है। अब अदालत के सामने चुनौती है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को पाक-साफ बनाये रखते हुए राजनीतिक शुचिता के आधार पर प्रजातंत्र की आत्मा संसद को मंदिर की तरह किस तरह पवित्र बनाया जाए। यानी संसद में हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर जाएं, जो भारत के सत्य, अहिंसा, प्रेम, परमार्थ और सद्भाव के संवैधानिक और सनातनी मूल्यों को समृद्ध कर अपने देश को एक तरक्की-पसंद और खुशहाल राष्ट्र के रूप में किस तरह विकसित करें? लेकिन विडंबना ही नहीं, बल्कि बेहद दुखदायी और कड़वी सच्चाई यह है कि पिछले कुछ दशकों से सोने की चिड़िया वाला हमारा यह देश तेजी से राजनीतिक रसातल की ओर बढ़ रहा है। पहले तो राजनीति का अपराधिकरण होता था लेकिन अब अपराध का राजनीतिकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि देश एक खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है। हाल में सुप्रीम कोर्ट में मय प्रमाण एफ़ीडेविट के साथ प्रस्तुत एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संसद के कुल 763 सांसदों में से 306 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसमें से 194 के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास तथा महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरण दर्ज हैं। राज्यसभा के 40 सांसदों पर संगीन अपराध कायम है। केरल जैसे पूर्ण साक्षर और शिक्षित राज्य में सबसे ज्यादा 73 प्रतिशत सांसदों पर केस दर्ज हैं। यानी कुल 29 सांसदों में से 23 सांसदों पर जुर्म दर्ज है। इसी तरह इसके पूर्व भी अदालत में जनहित याचिका में बताया गया है, कि जनता-जनार्दन के द्वारा चुने जाने वाले नगरीय निकाय से लेकर संसद में बैठे ज्यादातर

जनप्रतिनिधियों का आपराधिक रिकार्ड डराने वाला है। राज्यसभा में 75 और लोकसभा में 251 सांसदों पर कई संगीन अपराध दर्ज हैं। आपराधिक रिकार्ड वाले यह सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जनता के लिए नीतियां और महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाते हैं। याचिका में यह चिंता भी जाहिर किया गया है कि संसद के साथ देश के 14 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें बंगाल और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। संसद की तरह विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में 4 हजार विधायकों पर भी कई संगीन अपराध दर्ज हैं। इतना ही नहीं देश में नगरीय निकायों और पंचायतों में भी हजारों निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसे हैं, जिन पर आपराधिक मामले कायम हैं। इसी तरह पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और विभिन्न दलों के हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं पर भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं या फिर वे आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। याचिका में सीजेआई से मांग की गई है, कि इस मामले में बेबाकी से नीर-क्षीर फैसले से जनता को अपराधियों के आतंक से जल्द राहत दिलाई जाए। देश में ऐसा स्वस्थ, निष्पक्ष और स्वतंत्र, अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए कि जनता-जनार्दन सभी प्रकार के चुनावों में आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशियों को वोट देने से गुरेज करें। धर्म, जाति, सम्प्रदाय, प्रांत, भाषा के नाम पर जो वोट मांगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। जनता भी चपटी-चपटी आदि के लाभ-लोभ के चुनाव जिताऊ संस्कृति से ऊपर उठकर वोट करे और साहस के साथ आपराधिक रिकार्ड वाले प्रत्याशियों का सामाजिक बहिष्कार करें। वर्तमान में भ्रष्टाचार और खुदगर्जी के गर्त में जा रहे देश को फिर से गौरवशाली सुनहरे अतीत में ले जाने के लिए जब तक सरकार और समाज इस चर्चित मामले में जागरूक नहीं होंगे तब तक स्थिति चिंताजनक बनी रहेगी। राजनीति के बढ़ रहे अपराधिकरण के लिए कांग्रेस और भाजपा ही प्रमुख जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि सभी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय पार्टियों के लोग भी जिम्मेदार हैं। राजनीति को दल-दल बनाने वाले राजनीतिक दलों में अधिकतर लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या फिर यह दल साहस के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दरकिनार करने का साहस नहीं जुटा पाते। सत्यमेव जयते और सत्यम् शिवम् सुंदरम् की हमारी संस्कृति को चरित्रार्थ करने जितना साहस दिखाने की जरूरत सरकार और दलों को है, उतनी ही हिम्मत जनता को भी दिखानी होगी।

जीवेत शरदः शतम्

जीवेत शरदः शतम्

जीवेत शरदः शतम्

23
August
Birthday

आपकी कका वाली छवि आज भी
हर छत्तीसगढ़िया के दिल में
खास जगह रखती है...



**जन्मदिन मुबारक
भूपेश बघेल जी!**

श्री भूपेश बघेल जी
पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



अरुण बघेल
दुर्ग, छत्तीसगढ़



स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
कासाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
कासाबेल, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
दुलदूला, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

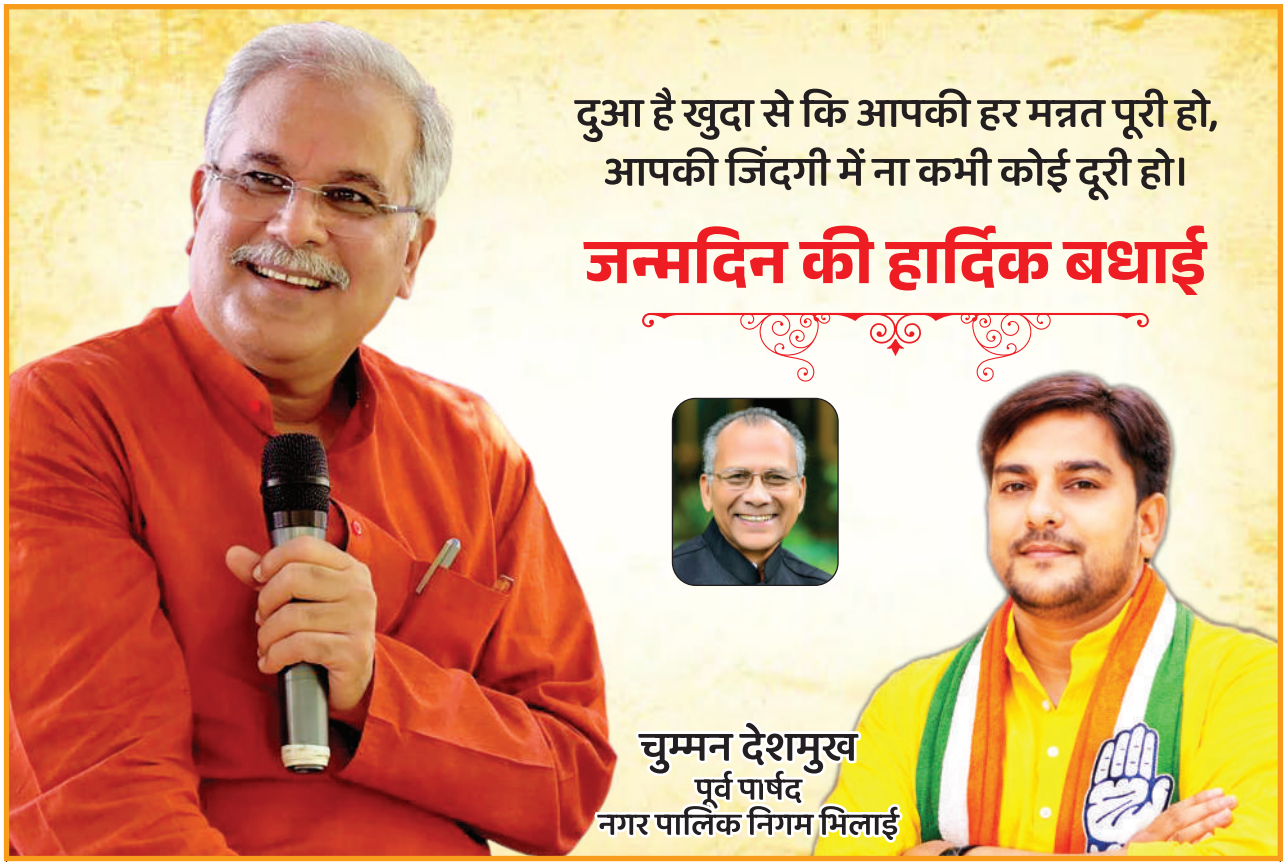


विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी
दुलदूला, जिला जशपुर (छ.ग.)

स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)



दुआ है खुदा से कि आपकी हर मन्नत पूरी हो,
आपकी जिंदगी में ना कभी कोई दूरी हो।

जन्मदिन की हार्दिक बधाई

चुम्पन देशमुख
पूर्व पार्षद
नगर पालिक निगम भिलाई



जन्मदिन की हार्दिक बधाई

फूलों की तरह महके
आपकी जिंदगी,
खुशियों से भर जाए
हर एक घड़ी।

चन्द्रभान सिंह ठाकुर
प्रदेश सचिव, छ.ग. आदिवासी कांग्रेस
जिलाध्यक्ष, छ.ग. आदिवासी विकास परिषद
पार्षद, रिसाली नगर निगम भिलाई



भिलाई में संगीत प्रेमियों के सर
चढ़ कर बोला रेडियो का जादू

छत्तीसगढ़ श्रोता मंच का अखिल भारतीय रेडियो श्रोताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन

आज 24 घंटे दिल और दिमाग के करीब रहने वाले सतरंगी सुपरफास्ट इंटरनेट के दौर में गुजरे जमाने के रेडियो के वक्त की बात ही कुछ और थी. शहर से महानगर और गांव से कस्बे तक जब रेडियो पर सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफी और सुरों की मलिका लता मंगेशकर के सुरीले नगमें गुंजते थे तो रोम-रोम रोमांचित हो जाता था. रेडियो की लोकप्रियता आम लोगों में इस कदर हावी थी कि चाहे आकाशवाणी रायपुर, जगदलपुर या फिर कोई भी केंद्र हो या फिर विविध भारती या रेडियो सिलोन और वॉयस ऑफ अमेरिका ही क्यों न हो. सभी के इंद्रधनुषी कार्यक्रमों का लोगों को बेसब्री से इंतजार ही नहीं होता था बल्कि सुने हुए कार्यक्रमों की यादें महीनों तरोताजा रहती थी. रेडियो श्रोता संघों और उद्घोषकों की आत्मा थी और आज जब रेडियो के सैकड़ों दीवाने एक छत के नीचे इकट्ठे हुए तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी.

» सतीश कुमार चौहान

यह यादगार मौका था महात्मा गांधी कलामंदिर में आयोजित अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का. छग श्रोता संघ के बैनर तले श्रोता दिवस पर हुए दो दिवसीय यादगार आयोजन में 18 राज्यों के तीन सौ से अधिक श्रोता संघों के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों और उद्घोषकों ने रेडियो के कार्यक्रमों के यादगार अनुभवों से भावविभोर कर दिया. समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल थे और अध्यक्षता प्रदेश भाजपा के प्रांतीय कार्यालय प्रभारी व सूचना प्रसारण विभाग के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य अशोक बजाज ने की. छग रेडियो श्रोता मंच के संरक्षक परसराम साहू, विविध भारती केंद्र मुंबई के डायरेक्टर संतोष जाधव, आकाशवाणी रायपुर के डायरेक्टर पंकज मेश्राम व उद्घोषक दीपक हटवार थे.

रेडियो प्रदर्शनी में भूले - बिसरे
दौर की यादें की तरोताजा

सांसद विजय बघेल ने कहा कि मेरी जन्म व कर्मभूमि भिलाई में देशभर से रेडियो श्रोता संघ के पदाधिकारी इस सम्मेलन में पहुंचे हैं, इसकी मुझे अतीव प्रसन्नता हो रही है. हम सबके बड़े होने तक मनोरंजन के माध्यम में ग्रामोफोन से लेकर विडियो व और अब नेट तक कई बदलाव हुए हैं, लेकिन रेडियो की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है. रेडियो श्रोता इसी तरह अपनी दोस्ती बढ़ाते रहें और अपने उत्साह को कम न होने दें. श्री बजाज ने कहा कि रेडियो से हमारी सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं. श्रोता संघ देशभर में फैला है. रेडियो श्रोता हिंदी को देश में संपर्क भाषा बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है. इसके जरिए हम पीएम मोदी के “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की मंशा को ओर आगे बढ़ा सकते हैं. उनकी “मन की बात” प्रसारण से भी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ रही है. हम आज रेडियो के फूहड़ गीतों से नई पीढ़ी के बच्चों

को बिगाड़ने के दुष्प्रयासों के खिलाफ भी जनजागरण करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रोता व उद्घोषक एक दूसरे के पूरक हैं। हम जल्द ही देश में रेडियो श्रोता महासंघ का गठन करेंगे, इसके लिए श्रोता अपने नाम- पते दें, ताकि रूपरेखा तैयार की जा सके। मंचस्थ अतिथियों ने श्रोता संघों के पदाधिकारियों को स्मृतिचिन्ह देकर सम्मान किया। इस अवसर पर छग श्रोता मंच आयोजन समिति के अशोक श्याम कुंवर, तारक सत्यदेव, डॉ. नौशाद सिद्दीकी, प्रताप पांडेय, सतीश चौहान, आनंदमोहन बाइन, मुकेश शर्मा, कृष्णचंद सोनी, रविलाल सूर्यवंशी, प्रदीप भट्टाचार्य, ललित बिजौरा सहित सैकड़ों रेडियो प्रेमी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन तारक सत्यदेव ने किया।

आकाशवाणी केंद्रों के उद्घोषकों का सम्मान

समापन समारोह में अध्यक्ष अशोक बजाज ने छग के आकाशवाणी

केंद्रों के उद्घोषकों को सम्मानित किया। सभी ने रेडियो के रोचक अनुभव भी साझा किए। उद्घोषक दीपक हटवार, हरिप्रिया पाणिग्रही, कल्पना सिन्हा, तरुण कुमार, विजय कुमार, राजकुमार आदि रायपुर, जगदलपुर व अंबिकापुर केंद्रों के उद्घोषकों का सम्मान हुआ। सम्मेलन में छग, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटक सहित 18 राज्यों के राज्यों के रेडियो श्रोता के प्रतिनिधि शामिल हुए। लोककलाकारों ने लोकरंगी प्रस्तुति दी। आनंदमोहन बाइन व एलसी कश्यप भिलाई और चंद्रपुर के चंद्रशेखर खुटमारे के रेडियो, ट्रांजिस्टर, बुक्स, उपकरणों आदि की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्री बाइन ने बताया कि कलेक्शन या रेडियो की मनोरंजन व सूचनापरक जानकारी युवावस्था से कर रहे हैं। दो बेटी सपना व रीपा भी मदद करती हैं। श्री कश्यप ने बताया कि रेडियो का शौक बचपन से है। सुबह श्रोताओं की निकली रैली में खासा उत्साह था।

आम आदमी की सुरीली घड़कन था रेडियो

भारत में पहला संगठित रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को 'इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी' (IBC) के तहत बंबई (मुंबई) स्टेशन से शुरू हुआ था। इसका ध्येय वाक्य "बहुजन हिताय बहुजन सुखाय" और इससे पहले जून 1923 में 'रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे' ने देश में पहली बार प्रायोगिक तौर पर कार्यक्रम प्रसारित किया था। इसकी शुरुआत बम्बई (मुंबई) और मद्रास (चेन्नई) केंद्रों से हुई थी। रेडियो सिलोन श्रीलंका (पुराना नाम सिलोन) में स्थित एशिया का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, जिसकी शुरुआत सन 1923 में हुई थी। 1950 और 1960 के दशक में यह दक्षिण एशिया में हिंदी फिल्मों के संगीत और लोकप्रिय कार्यक्रमों (जैसे 'बिनाका गीतमाला') का सबसे बड़ा केंद्र था।

आकाशवाणी रायपुर के 'सुरसिंगार' कार्यक्रम ने छत्तीसगढ़ी गीतों को पूरे देश में मीठी जुबान बना दिए थे, 'आपके मीत ये गीत' और 'युववाणी' युवाओं में काफी लोकप्रिय था, शाम सात बजे 'चौपाल' कार्यक्रम बरसाती भैया (केसरी प्रसाद वाजपेयी) की सरल भाषा में मनोरंजन के साथ खेती की उन्नत तकनीक बताना काफी लाभप्रद रही। कार्यक्रम 'युववाणी' और 'आज मेरी बारी है' में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। लाल रामकुमार सिंह, किशन गंगोले, मिर्जा मसूद, कल्पना यादव, प्रभा डामोर, लक्ष्मेन्द्र चोपड़ा, तेजिन्दर सिंह गगन, लीलाधर मंडलोई, कमल शर्मा जैसे उद्घोषकों के नाम आज भी लोग याद करते हैं, विविध भारती की छायागीत, हवामहल और जवानों के लिये 'जयमाला' आज भी लोकप्रिय हैं। 1947 के बटवारे के तुरंत बाद दोनों देशों के भाईचारे की बेबसी और घुटन पर ऑल इंडिया की उर्दू सर्विस द्वारा प्रसारित साप्ताहिक कार्यक्रम 'आवाज दे कहाँ है' सुनकर लोग बाघा बार्डर की ओर दौड़ पड़ते थे, कई बिछड़े परिवारों व मित्रों को मिलवाया। सत्तर-अस्सी के दौर में श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानि रेडियो सिलोन के बारे में तो जितना कहा जाये कम है सुबह 6 बजे से वंदना के बाद शुरू सभा पुराने गीत, फिर आप ही के

गीत जैसे कार्यक्रम एक बेहतर गुडमॉर्निंग होते थे, अमीन सायानी द्वारा प्रस्तुत बिनाका गीतमाला की लोकप्रियता का ये आलम था कि मुंबई फिल्म उद्योग से निर्माता निर्देशक, गीतकार, गायक व संगीतकार अपने गीतों को सरताज गीत बनाने के लिये देश भर के रेडियो श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा फरमाईश भेजने के लिये निवेदन करने लगे थे, रेडियो सिलोन को शाम का प्राइम टाइम संडे सुबह की सभा पूरे समय श्रोताओं को बांधे रखती थी। वाक्यों के शब्दों पर आधारित 'वाक्य गीतांजलि' कार्यक्रम में एक हजार वाक्यों के चयन पर भिलाई के ही एक श्रोता प्रदीप शाह लिम्का बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला था। साप्ताहिक कार्यक्रम 'हफ्ते के श्रोता' पत्र मित्रता का बेमिसाल कार्यक्रम इसी तरह बदलते साथी, भावना प्रधान भावगीत कार्यक्रम, जब आप गा उठे, आपकी बधाईयां, जोहार के जवाब, मराठा दरबार की महकती यादें, तबस्सुम के ठहाके, मतलब स्वस्थ मनोरंजन की मिसाल। शशि परेरा, विजयलक्ष्मी, मनोहर महाजन, रिपुसूदन कुमार ऐलावादी, दलवीर सिंह परमार जैसे कई उद्घोषक की आवाजें हवा में मिश्री घोलती थी, बीबीसी लन्दन के समाचार तो आज भी स्टोन मार्क माने जाते हैं।

एक दौर ऐसा भी था कि पूरे देश में रेडियो श्रोता संघों का गठन होने लगा था, रेडियो क्लब बन गये। कार्यक्रमों में श्रोताओं की भागीदारी होने लगी। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में तो श्रोताओं की बड़ी तादाद आज भी रेडियो में जुड़ी हैं। झूमरीतलैया, भाटापारा, सीतामढ़ी, भिलाई, अकोला, बुलढाणा, डोंगरगढ़, रिंगनी, धमतरी ऐसे कुछ शहर के नाम हर समय कहीं ना कहीं रेडियो के नाम से गूंजते रहते हैं। सत्तर के दशक से रेडियो से श्रोता के रूप में जुड़े खुर्सीपार भिलाई के सतीश चौहान आज भी आकाशवाणी रायपुर, विविध भारती, रेडियो सिलोन, ऑल इंडिया रेडियो और एफ एम बैंड में हिस्सा लेते रहते हैं।

(लेखक 40 वर्षों से रेडियो श्रोता हैं और नियमित रूप से जुड़े हैं।)



नई पीढ़ी को अपनी परंपरा, भाषा और कला से जोड़ते लोकपर्व

छत्तीसगढ़ की संस्कृति भारतीय लोक-संस्कृति की एक समृद्ध एवं विशिष्ट धारा है। इसकी पहचान लोकभाषा, लोकगीत, लोकनृत्य, लोककला, लोकपरंपरा, कृषि-आधारित जीवन-पद्धति तथा सामुदायिक जीवन-मूल्यों से निर्मित हुई है। छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहार इस सांस्कृतिक संरचना को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरेली, तीजा, पोला, भोजली, छेरछेरा, गौरा-गौरी, कमरछठ, नवाखाई तथा बस्तर दशहरा जैसे पर्व केवल धार्मिक अथवा मनोरंजनात्मक आयोजन नहीं हैं, बल्कि वे लोकजीवन की सामूहिक स्मृति, सामाजिक एकता, कृषि-परंपरा, प्रकृति-प्रेम, लोककला और लोकभाषा के संरक्षण के प्रभावी माध्यम हैं।



» सहदेव देशमुख

संस्कृति किसी समाज की जीवन-पद्धति का समग्र रूप है। इसमें भाषा, साहित्य, कला, धर्म, रीति-रिवाज, मान्यताएँ, खान-पान, वेशभूषा, लोकविश्वास तथा सामाजिक व्यवहार सम्मिलित होते हैं।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति का मूल आधार लोकजीवन है। ग्रामीण एवं आदिवासी जीवन की परंपराओं ने इसके स्वरूप को गहराई प्रदान

की है। यहाँ की संस्कृति में प्रकृति के प्रति सम्मान, श्रम के प्रति आदर, सामुदायिक सहयोग और पारिवारिक संबंधों को विशेष महत्व प्राप्त है।

इसीलिए छत्तीसगढ़ के पर्वों में व्यक्ति की अपेक्षा समुदाय और प्रकृति के साथ उसके संबंध को अधिक महत्व मिलता है।

छत्तीसगढ़ को लंबे समय से कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ की कृषि-आधारित जीवन-पद्धति का प्रभाव पर्वों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

हरेली

हरेली छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकपर्व है। यह हरियाली, कृषि और प्रकृति से जुड़ा पर्व है। इस अवसर पर कृषि उपकरणों तथा पशुधन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। हरेली यह संदेश देता है कि मनुष्य का जीवन प्रकृति और कृषि से गहराई से जुड़ा हुआ है।

पोला

पोला पर्व मुख्यतः कृषि कार्यों में बैलों के महत्व को स्वीकार करने वाला पर्व है। बैल किसान के जीवन और कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। पोला के माध्यम से पशुधन के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना व्यक्त होती है।



नवाखाई

नई फसल के आगमन से जुड़े पर्व कृषि जीवन की समृद्धि और प्रकृति के प्रति आभार की अभिव्यक्ति हैं। नई उपज को सामुदायिक जीवन से जोड़ना कृषि संस्कृति की सामाजिक महत्ता को दर्शाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी पर्व कृषि को केवल आर्थिक गतिविधि न मानकर जीवन और संस्कृति का आधार मानते हैं।

लोकगीत-लोकनृत्य के संरक्षण में योगदान

छत्तीसगढ़ी लोकपर्व लोकगीतों और लोकनृत्यों के विकास के प्रमुख अवसर प्रदान करते हैं। तीजा, भोजली, गौरा-गौरी तथा अन्य पर्वों के अवसर पर पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति होती है।

लोकगीतों में प्रेम, विरह, पारिवारिक संबंध, कृषि, प्रकृति, सामाजिक जीवन और धार्मिक आस्था जैसे अनेक विषय अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार करमा, सुआ, राउत नाचा और पंथी जैसे लोकनृत्य सामूहिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। पर्वों के कारण इन लोककलाओं को सामाजिक मंच मिलता है और वे नई पीढ़ी तक पहुँचती हैं।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण में पर्वों की भूमिका

भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है। छत्तीसगढ़ी पर्वों के गीतों, लोककथाओं, कहावतों और पारंपरिक संवादों में छत्तीसगढ़ी भाषा का सहज एवं स्वाभाविक प्रयोग होता है। पर्वों के अवसर पर परिवार के बच्चे और युवा जब बुजुर्गों से लोकगीत एवं परंपराएँ सीखते हैं, तब उनके साथ भाषा की विशिष्ट शब्दावली और लोक-अभिव्यक्तियाँ भी अगली पीढ़ी तक पहुँचती हैं। इस प्रकार पर्व छत्तीसगढ़ी भाषा के मौखिक संरक्षण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

सामाजिक एकता और सामुदायिक भावना

छत्तीसगढ़ी पर्वों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी सामूहिकता है। पर्व व्यक्ति को परिवार से और परिवार को समुदाय से जोड़ते हैं। सामूहिक पूजा, सामूहिक नृत्य, लोकगीत, भोज तथा मेल-मिलाप के माध्यम से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। छेरछेरा जैसे पर्वों में परस्पर सहयोग और साझेदारी की भावना विशेष रूप से दिखाई देती है। पर्वों के माध्यम से समाज में सहयोग, सद्भाव, सहभागिता और भाईचारे के मूल्य विकसित होते हैं।

महिलाओं की भूमिका

छत्तीसगढ़ी लोकसंस्कृति के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीजा, भोजली और कमरछठ जैसे पर्वों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रहती है। महिलाएँ पारंपरिक गीतों को याद रखती हैं, नई पीढ़ी को सिखाती हैं और पारंपरिक रीति-रिवाजों को सामाजिक जीवन में बनाए रखती हैं। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ी पर्व महिलाओं को केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं जोड़ते, बल्कि उन्हें लोकसंस्कृति की प्रमुख वाहक के रूप में स्थापित करते हैं।

प्रकृति और पर्यावरण चेतना

छत्तीसगढ़ी पर्वों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा का भाव दिखाई देता है। कृषि, वर्षा, पेड़-पौधे, पशुधन और भूमि के साथ मनुष्य के संबंध को पर्वों के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है। हरेली जैसे पर्व हरियाली और कृषि जीवन से जुड़े हैं, जबकि पशुधन से संबंधित पर्व मनुष्य और पशु के पारस्परिक संबंध को रेखांकित करते हैं। आज जब पर्यावरणीय संकट गंभीर रूप ले रहा है, तब इन लोकपर्वों में निहित प्रकृति-सम्मान की भावना आधुनिक समाज के लिए भी उपयोगी संदेश प्रस्तुत करती है।

लोकशिल्प एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

पर्वों के अवसर पर स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ती है। मिट्टी के खिलौने, बाँस की वस्तुएँ, पारंपरिक सजावटी सामग्री, लोक आभूषण तथा अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएँ लोकपर्वों के सांस्कृतिक परिवेश का हिस्सा बनती हैं। इससे स्थानीय शिल्पकारों को आर्थिक अवसर मिलते हैं और पारंपरिक हस्तशिल्प की निरंतरता बनी रहती है। अतः पर्व सांस्कृतिक गतिविधि के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देते हैं।



सांस्कृतिक अस्मिता और नई पीढ़ी

आधुनिकता, शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण स्थानीय संस्कृतियों के सामने अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे समय में लोकपर्व सांस्कृतिक अस्मिता के महत्वपूर्ण आधार बन जाते हैं। पर्वों में युवा पीढ़ी की भागीदारी बढ़ने से उन्हें अपनी भाषा, परंपरा और लोककलाओं से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे उनमें अपनी संस्कृति के प्रति आत्मगौरव की भावना विकसित होती है। इसलिए आधुनिकता का विरोध किए बिना लोकपर्वों को आधुनिक माध्यमों के साथ जोड़ना आवश्यक है।

बस्तर दशहरा और सांस्कृतिक विविधता

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता का एक विशिष्ट उदाहरण बस्तर दशहरा है। इसकी परंपराएँ स्थानीय सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से गहराई से जुड़ी हैं। यह पर्व छत्तीसगढ़ के जनजातीय सांस्कृतिक संसार की विशिष्टता को सामने लाता है। बस्तर दशहरा यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति एकरूप नहीं है, बल्कि अनेक लोकपरंपराओं, समुदायों और सांस्कृतिक अनुभवों का समन्वित रूप है।



आधुनिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ी पर्व

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ी पर्वों का स्वरूप भी परिवर्तनशील है। संचार माध्यमों, सोशल मीडिया, सांस्कृतिक मंचों और विद्यालय-महाविद्यालयों के आयोजनों ने इन पर्वों को व्यापक सार्वजनिक पहचान प्रदान की है।

हालाँकि आधुनिकता के कारण कुछ पारंपरिक रूपों में परिवर्तन भी आया है। इसलिए आवश्यक है कि पर्वों का आधुनिकीकरण उनकी मूल लोकभावना को समाप्त किए बिना हो।

पारंपरिक गीतों का दस्तावेजीकरण, लोककलाकारों को प्रोत्साहन, विद्यालयों में लोकसंस्कृति संबंधी कार्यक्रम तथा डिजिटल माध्यमों पर प्रमाणिक लोकसामग्री का प्रसार इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ी पर्व छत्तीसगढ़ की संस्कृति के जीवंत दस्तावेज हैं। इनमें केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि लोकजीवन का अनुभव, कृषि संस्कृति, प्रकृति-प्रेम, सामाजिक संबंध, सामुदायिक सहयोग और लोककलाओं की सृजनात्मक शक्ति समाहित है।

हरेली में हरियाली और कृषि जीवन का सम्मान दिखाई देता है, पोला में पशुधन के प्रति कृतज्ञता, तीजा और भोजली में लोकजीवन की भावनात्मक अभिव्यक्ति, छेरछेरा में सामाजिक साझेदारी तथा बस्तर दशहरा में सांस्कृतिक विविधता का विराट स्वरूप दिखाई देता है।

ये पर्व अतीत के गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की जीवंतता के बीच एक अटूट सेतु का निर्माण करते हैं। यह हमारी समृद्ध लोक-संस्कृति की निरंतर विकास-यात्रा को नई गति और दिशा प्रदान करते हैं। अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटती नई पीढ़ी को यह माटी के संस्कारों, लोक-मूल्यों और आत्मीयता से जोड़ने का काम करते हैं। जब तक इन पर्वों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण, संरक्षण और संवर्धन पूर्ण निष्ठा के साथ नहीं किया जाएगा, तब तक छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक-संस्कृति के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी ही रहेगी।



छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा छत्तीसगढ़िया मन के मान बढ़इया भूपेश भैया, हमर भूपेश भैया

भूपेश बघेल जी के कार्यकाल
में हुए महत्वपूर्ण कार्य



- लगभग 18 लाख किसानों का 10000 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया
- विजिली बिल हॉफ योजना
- किसानों का लगभग 350 करोड़ सिंचाई कर माफ किया गया
- 2500 रुपये से अधिक कीमत पर प्रति बिंदेल खान खरीदने वाला पहला राज्य
- किसानों का धान प्रति एकड़ 20 बिंदेल खरीद गया
- राम वन गमन पर्यटन परिषद का विकास
- शहीद महेंद्र कर्मा मैदूपाता संग्रहालय सांसाजिक सुरक्षा योजना
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- गोधन न्याय योजना
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि भूजदूर न्याय योजना
- 65 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी
- मुख्यमंत्री हर बाजार वनीकरण योजना
- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना
- डॉ. खुर्वांद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना
- छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- छत्तीसगढ़ के सभी धौल उपभोक्ताओं को विजिली बिल हॉफ योजना के तहत लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3500 करोड़ की छूट दी गई है
- मुख्यमंत्री मितान योजना, हेरली, तीजा, मां कर्मा जयंती, विरव आदिवासी दिवस, छठ पूजा की अवकाश
- मुख्यमंत्री शहरी रसम योजना, पढ़ई तुहर दुआर योजना
- स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना
- 2500 रुपये युवा वैरोजगारी भता

आंगनवाड़ी, मितानिन, स्कूल रसोइया,
स्कूल सफाई कर्मचारी मन के मानदेय बढ़इया
मान. भूपेश बघेल जी ला जन्मदिन के गाड़ा-गाड़ा बधाई



भूपेश भैया
आय जियो हजारों साल



मिरीश देवांगन
पूर्व अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
(पूर्व केबिनेट मंत्री दर्जा)

सुशील सन्नी अग्रवाल
पूर्व अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ भवन एवं
अन्य तंत्रिकाय कर्मकार कल्याण मंडल, BOCW
(पूर्व केबिनेट मंत्री दर्जा)

कमजोर विपक्ष की मजबूती

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है परंतु सत्ता पक्ष को जनता की अभिव्यक्ति से अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आता है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है। सत्ता पक्ष विपक्ष मुक्त भारत चाहता है फिर भी वे अपने आपको लोकतंत्र का हिमायती बताते हैं। 2014 में देश का विपक्ष इतना कमजोर हो गया था कि उसे विपक्ष की मान्यता भी नहीं मिली थी।



» राजशेखर चौबे

सत्तारूढ़ दल के तंगदिल नेता मान्यता दे सकते थे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हमारे देश की पूरी ऊर्जा सत्ता पक्ष की तारीफ और विपक्ष की बुराई में जाया हो रही है। विपक्ष की इतनी बुराई की गई है कि वह अपने आप को अच्छा भी नहीं कह पा रहा है इसीलिए वे सत्ता पक्ष की बुराई या

आलोचना कर अपना वजूद बचाने में लगे हैं। विरोधियों को चमचा बताया जाता है जबकि चमचागिरी या चाटुकारिता तारीफ करके ही की जा सकती है आलोचना द्वारा नहीं। इस हिसाब से सत्ता पक्ष के समर्थक ही चमचे या चाटुकार कहे जा सकते हैं। आजकल हम शर्म की बात पर भी गर्व करने लगे हैं। हम अंधभक्ति या चमचई पर भी गर्व करने लगे हैं। वे गर्व करते हैं और कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते।

सत्ता पक्ष के लोग और उनके समर्थक देश में विपक्ष नहीं चाहते हैं। वे प्रसन्न हैं कि देश में विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है फिर भी विपक्ष का ऐसा डर पहले कभी नहीं दिखा। भले ही विपक्ष कमजोर है फिर भी वह देश में घुसपैठ कराने में सफल है। उसने लाखों विदेशियों को देश में लाकर बसा दिया है जिसे यह ताकतवर सरकार निकाल नहीं पा रही है। खास खास राज्यों में चुनाव के दौरान ही घुसपैठिये बढ़ जाते हैं फिर चुनाव के बाद गायब भी हो जाते हैं। है न जादू !

देश में पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन यह इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। यह विपक्ष की नाकामी है। पहलगाम



में पर्यटकों को मार दिया जाता है, यह भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है फिर भी छत्तीसगढ़ के श्रमिक मारे जाते हैं। सरकार से सवाल करने वाले देश विरोधी माने जाते हैं और विपक्ष से सवाल करने वाले देशभक्त। सत्ता पक्ष वाले देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।

विपक्ष कमजोर है परंतु देश के विरुद्ध

षडयंत्र कर लेता है। सत्ता पक्ष मजबूत है लेकिन वह षडयंत्र को रोक नहीं पाता है। विपक्ष कमजोर है लेकिन विदेशी फंडिंग जुटा लेता है। इसे भी सत्ता पक्ष रोक नहीं पाता है। विपक्ष कमजोर है लेकिन जंतर मंतर में लाखों जुझारू Gen Z के छात्र जमा कर लेता है और करोड़ों लोगों को सरकार का विरोध करने के लिए प्रेरित कर लेता है। मजबूरन इस उदार और दयालु सरकार को लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ता है। यहां तक कि पेलेट गन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कमजोर विपक्ष शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले लेता है। इतने कमजोर विपक्ष से भी मजबूत सत्ता पक्ष वाले डर गए हैं।

देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष सवाल पूछ पूछ कर सत्ता पक्ष को काम नहीं करने देता इसीलिए सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो रही है। कमजोर विपक्ष सक्षम है विदेशियों से सांठ-गांठ करने में, विदेशी फंडिंग जुटाने में, देश के विरुद्ध षडयंत्र करने में, घुसपैठ करवाने में, जंतर-मंतर में लाखों छात्रों को जुटाने में, करोड़ों लोगों को विरोध करने के लिए प्रेरित करने में ! देश का विपक्ष सभी काम कर सकता है सिवाय एक काम के और वह काम है - चुनाव जीतना !!

(लेखक, सेवानिवृत्त, सहायक आयुक्त, भारतीय राजस्व सेवा हैं.)



छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी
को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं...
आपकी **नेतृत्व क्षमता** और निर्णय लेने का
साहस अनुकरणीय है...



भूपेन्द्र कश्यप
पूर्व अध्यक्ष, नगर पंचायत पाटन
जिला दुर्ग (छ.ग.)



सरल सुगम सशक्त



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

प्रशासनिक सुधार और नवाचार

प्रगति और समृद्धि का सपना हो रहा साकार



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

प्रशासनिक सुधार



- सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना
- ई-गवर्नेंस को बढ़ावा, ई-ऑफिस प्रणाली
- अटल डैशबोर्ड
- मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप
- सीएम हेल्पलाइन 1076

राजस्व एवं पंजीयन सुधार



- प्रदेश में 119 पंजीयन कार्यालय बन रहे स्मार्ट
- भूमि विवाद रोकने जियो-रेफरेंसिंग
- 10 क्रांतियों और सुगम एप से आसान हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया
- वनाधिकार पट्टा वितरण से मिला मालिकाना हक

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस



- जन विश्वास 2.0 लागू करने वाला पहला राज्य
- इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ पोर्टल के वन-क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से त्वरित स्वीकृति
- स्टार्टअप एवं नवाचार नीति 2025-30 लागू
- भारत सरकार द्वारा LEADS 2025 में लैंडलॉक्ड राज्यों में हाई परफॉर्म की मान्यता

सेवाओं का डिजिटलीकरण



- 6,000+ पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र
- सेवा सेतु से 661 से अधिक सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
- अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुगम प्रक्रिया

भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं पारदर्शिता



- जेम पोर्टल से सरकारी खरीदी
- भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और नकल के विरुद्ध कठोर कानून
- खनिज ट्रांजिट पास की प्रक्रिया हुई पारदर्शी
- लकड़ी व खनिज ब्लॉक की पारदर्शी ई-नीलामी